



लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद,आजमगढ़, अयोध्या, झांसी,अम्बेडकरनगर, एटा,औरैया, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, उन्नाव, लखीमपुर, मुगदाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, सीतापुर,गौनपुर,श्रावस्ती,उरई,जालौन, फिरोजगढ,हरदोई, मथुरा,कानपुर,ललितपुर, गोण्डा, सहारनपुर,सिद्धार्थनगर,सन्तकबीरनगर, नोयडा, सुलतानपुर, कासगंज सहित प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में बहुप्रससित

वर्ष : 14 अंक 347

लखनऊ, रविवार, 06 जुलाई 2025

पृष्ठ : 8

मूल्य : 2.00

संक्षिप्त

भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी का भाई नेहल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार

नई दिल्ली। भगोड़े हीरा व्यापारी और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के एक मुख्य आरोपी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका के न्याय विभाग ने नेहल मोदी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी भारतीय एजेंसियों केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)और प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर की गयी है। नेहल मोदी पर देश के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में नीरव मोदी से संबंधित सबूतों को छिपाने , गवाहों को धमकाने और पैसों को छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है। सूत्रों ने कहा कि अब नेहल मोदी के भारत प्रत्यर्पण की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ तालमेल किया जायेगा।

हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी की दरखास्त खारिज

मऊ। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की एक विशेष अदालत ने हेट स्पीच मामले में पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की दोषसिद्धि के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि हेट स्पीच के मामले में पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को 31 मई को स्थानीय न्यायालय ने दोषसिद्ध करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने आरोप जिला जज/एमपी एमएलए कोर्ट में दोषसिद्धि के खिलाफ दरखास्त दाखिल की थी। इसके साथ ही जमानत को बरकरार रखने के अपील की गई थी। शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट जज राजीव कुमार वक्स ने हेट स्पीच के मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अब्बास अंसारी की दरखास्त खारिज कर दिया है। हालांकि उनकी जमानत बरकरार रहेगी।

महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध अनुचित : अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में हिन्दी भाषा के मामले में मारपीट की निंदा करते हुए शनिवार को कहा कि देश की सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए मगर हिन्दी भाषी लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। श्री यादव ने शनिवार को यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र में हिन्दी भाषा का विरोध सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है जो गलत है। भाजपा की मंशा समाज में खाई पैदा कर राजनीतिक लाभ उठाना है।

भारत में 40 लाख कर्मचारी और 80 लाख बोर्ड सदस्य सहकारी गतिविधियों से जुड़े हैं : शाह

● **अमित शाह ने आणंद में त्रिभुवन सहकारिता विवि का शिलान्यास किया**

एजेंसी

गांधीनगर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आणंद में त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते हुए कहा कि आने वाले समय में सहकारी गतिविधियों का विस्तार होना तय है। टैक्सी सेवा और बीमा सेवा जैसे क्षेत्रों में सहकारी मॉडल लागू करने की योजना के अंतर्गत इस विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित मानव



लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद,आजमगढ़, अयोध्या, झांसी,अम्बेडकरनगर, एटा,औरैया, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, उन्नाव, लखीमपुर, मुगदाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, सीतापुर,गौनपुर,श्रावस्ती,उरई,जालौन, फिरोजगढ,हरदोई, मथुरा,कानपुर,ललितपुर, गोण्डा, सहारनपुर,सिद्धार्थनगर,सन्तकबीरनगर, नोयडा, सुलतानपुर, कासगंज सहित प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में बहुप्रससित

वर्ष : 14 अंक 347



लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद,आजमगढ़, अयोध्या, झांसी,अम्बेडकरनगर, एटा,औरैया, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, उन्नाव, लखीमपुर, मुगदाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, सीतापुर,गौनपुर,श्रावस्ती,उरई,जालौन, फिरोजगढ,हरदोई, मथुरा,कानपुर,ललितपुर, गोण्डा, सहारनपुर,सिद्धार्थनगर,सन्तकबीरनगर, नोयडा, सुलतानपुर, कासगंज सहित प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में बहुप्रससित

वर्ष : 14 अंक 347



लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद,आजमगढ़, अयोध्या, झांसी,अम्बेडकरनगर, एटा,औरैया, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, उन्नाव, लखीमपुर, मुगदाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, सीतापुर,गौनपुर,श्रावस्ती,उरई,जालौन, फिरोजगढ,हरदोई, मथुरा,कानपुर,ललितपुर, गोण्डा, सहारनपुर,सिद्धार्थनगर,सन्तकबीरनगर, नोयडा, सुलतानपुर, कासगंज सहित प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में बहुप्रससित

वर्ष : 14 अंक 347



लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद,आजमगढ़, अयोध्या, झांसी,अम्बेडकरनगर, एटा,औरैया, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, उन्नाव, लखीमपुर, मुगदाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, सीतापुर,गौनपुर,श्रावस्ती,उरई,जालौन, फिरोजगढ,हरदोई, मथुरा,कानपुर,ललितपुर, गोण्डा, सहारनपुर,सिद्धार्थनगर,सन्तकबीरनगर, नोयडा, सुलतानपुर, कासगंज सहित प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में बहुप्रससित

वर्ष : 14 अंक 347

यूपी में अवैध धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश

अवैध मतांतरण का सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गिरफ्तार

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड (एटीएस) की टीम ने शनिवार को अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरोह के मुख्य आरोपित जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा समेत चार लोगों गिरफ्तार किया है। उसके गैंग में शामिल लोग प्रेमजाल में फंसाकर लड़कियों का धर्मांतरण करा रहे थे। इसके लिए उन्हें मोटी रकम मिलती थी और 40 अक्राउंट में विदेशों से करोड़ों की फंडिंग की गई है। एडीजी एलओ अभिताभ यश ने बताया कि जिला बलरामपुर के रेहरा माफी का रहने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपने आप को हजरत जलालुद्दीन पीर बाबा के नाम से प्रचारित करता था। उसके द्वारा जिले में धर्मांतरण गिरोह चलाने की बात सामने आयी थी। एसटीएफ की जांच में पता चला कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा

● **40 बैंक अक्राउंट में विदेशों से करोड़ों की फंडिंग के सबूत**

● **धर्मांतरण कराने के लिए एजेंटों को मिलती थी मोटी रकम**

तीन-चार वर्षों से नवीन घनश्याम रोहरा निवासी मुंबई, नवीन की पत्नी नीतू नवीन रोहरा, पुत्री समाले नवीन रोहरा के साथ रहता है। तीनों व्यक्ति मूलरूप से सिंधी हैं। छांगुर शाह ने सभी का ब्रेनवाश कर इस्लाम धर्म स्वीकार कराया। इसके बाद तीनों ने अपने नाम जमालुद्दीन, नसरीन एवं सबीहा रख लिया था। छांगुर बाबा ने शिजर-ए-तैय्यबा नाम से एक पुस्तक भी छपवा रखी है, जिसके माध्यम से इस्लाम



धर्म का प्रचार-प्रसार करता है। लखनऊ की एक युवती ने अबू अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। उसने बताया कि अबू ने अपना अमित बताकर उसे प्रेम जाल में फंसाया। उसे लेकर छांगुर बाबा के पास ले गया, जहां नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने उसका ब्रेनवाश इस्लाम धर्म स्वीकार

अर्जेन्टीना में भारतीय संस्कृति की झलक देख भावुक हुए मोदी



एजेंसी

ब्यूनस आयर्स/नई दिल्ली। अर्जेन्टीना में भारतीय समुदाय द्वारा किये गये स्वागत से भावविभोर हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश से हजारों किलोमीटर दूर भारतीय

संस्कृति की झलक देखकर मन भावुक हो गया। पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में श्री मोदी शनिवार सुबह ब्यूनस आयर्स पहुंचे जहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने कथक और अन्य नृत्य शैलियों के साथ सांस्कृतिक

कार्यक्रम प्रस्तुत किये। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, सांस्कृतिक संपर्क के लिए दूरी कोई बाधा नहीं है ! ब्यूनस आयर्स में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए शानदार स्वागत से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह देखना वास्तव में भावुक करने वाला है कि भारतीय समुदाय की बढौलत घर से हजारों किलोमीटर दूर भी भारत की भावना की झलक दिखायी दे रही है। प्रधानमंत्री की अर्जेन्टीना यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना है। वह अर्जेन्टीना के राष्ट्रपति जेविअर माइली के निमंत्रण पर आधिकारिक यात्रां पर यहां आये हैं।

बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

एजेंसी



संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21ए के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। रिट याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने नवंबर 2025 में होने वाले बिहार विधान सभा चुनावों के

आसपास राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण करने के लिए अनुचित और अत्यवहारिक समयसीमा जारी की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने अपने आदेश से मतदाता सूची में शामिल होने की जिम्मेदारी राज्य से नागरिकों पर डाल दी है। याचिका में दावा किया गया है कि आयोग के उक्त आदेश में

हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट, पांच जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिन लोगों को मानसून के कहर से सावधान रहना होगा। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी करते हुए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किए हैं। 6 जुलाई को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में बहुत भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही शिमला, मंडी, कांगड़ा, चम्बा और सिरमौर जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर फ्लैश फ्लड का गंभीर खतरा जाताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 6 से 9 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किए गए हैं। 6 जुलाई को लाहौल-स्पीति व किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी 7 जिलों -ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन में ऑरेंज अलर्ट रहेगा।

● **संयुक्त रैली में उद्धव का दावा-हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं**

मुंबई। उद्धव ठाकरे गुट (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) की संयुक्त रैली में उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि वे साथ रहने के लिए साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने उनकी इस्तेमाल करो और फेंको नीति का कड़वा अनुभव लिया, अब हम उन्हें राजनीति से बाहर फेंकेंगे। मुंबई के वली डोम में आयोजित इस संयुक्त रैली में उद्धव ठाकरे ने मनसे के साथ यूबीटी के गठबंधन की घोषणा की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कई सालों बाद राज ठाकरे और वे एक साथ

बिहार की 2003 की मतदाता सूची में शामिल न होने वाले मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए निर्दिष्ट नागरिकता दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है।वर्ष 2003 से बिहार में पांच आम चुनाव और पांच विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें मतदाता सूची में नामों को लगातार जोड़ा और हटया गया है। याचिका में इसके अलावा, 29 अक्टूबर, 2024 और छह जनवरी, 2025 के बीच विशेष सारांश संशोधन पहले ही किया जा चुका है, जिसमें मृत्यु या अन्य कारणों से प्रवास और अयोग्य मतदाताओं जैसे मुद्दों का निपटारा किया गया था। इस तरह इतने कम समय में चुनौती राज्य बिहार में इस तरह के विशेष गहन पुनरीक्षण करने का कोई कारण नहीं है, जो लाखों मतदाताओं के वोट के अधिकार का उल्लंघन करता है।

याचिका में यह भी दलील दी गई है कि बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां बड़ी संख्या में लोगों का पलायन होता है। ऐसे में यहां की एक बड़ी आबादी के पास जन्म प्रमाण पत्र या अपने माता-पिता से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। याचिका में आशंका जतायी गयी है कि चुनाव आयोग के ताजा आदेश से राज्य के तीन करोड़ से अधिक लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।

विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और प्रवासी श्रमिक शामिल इसे प्रभावित होंगे। याचिकाकर्ता ने अयालत से गुहार लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के जून में जारी उक्त आदेश को रद्द कर दिया जाए। यदि इसे रद्द नहीं किया गया तो मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया अपनाने बिना लाखों लोगों को अकेले मताधिकार से वंचित किया जा सकता है।

योगी सरकार किसानों को बना रही ब्रांड एंबेसडर

● **प्राकृतिक खेती को मिलेगी नई पहचान, किसानों को मिलेगा प्रचार-प्रसार का अवसर**

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योगी सरकार ने नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 200 प्राकृतिक-कृषि किसानों का चयन किया गया है, जिन्हें अब ब्रांड एंबेसडर के रूप में तैनात किया जाएगा। इस कदम का मकसद किसानों को जागरूक बनाना और प्राकृतिक खेती को एक नई पहचान देना है। इस योजना के तहत, किसानों को ट्रेनिंग-ऑफ-ट्रेनर्स (इट्ट) मॉडल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले बैच के प्रशिक्षकों को



सार्वजनिक मंच पर मिले।

हम सभी ने उनकी उपलब्धियां देखी हैं। हर बार यह सवाल उठाया गया था कि क्या हम एक साथ आएंगे। अब हम साथ आए हैं, लोग हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा मिलन मराठी के लिए नहीं बल्कि नगर निगम के लिए है। हालांकि,

धर्मांतरण कराते है। बात न मानने पर मुकदमा दर्ज कराने का दबाव भी देते हैं। एटीएस को यह भी जानकारी मिली है कि आजमगढ़ के थाना देवगांव में छांगुर बाबा के सहयोगियों, रिश्तेदारों के विरुद्ध अवैध धर्मांतरण के आरोप में मुकदमा दर्ज हैं।

इसी मंगलवार को विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने कथित पीर छांगुर बाबा पर गंभीर आरोप लगाए थे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने दावा किया था कि छांगुर बाबा ने हजारों हिंदुओं को फजी चमत्कारों, धन के लालच और डर का इस्तेमाल कर इस्लाम कबूल करवाया है। उसे अवैध फंडिंग होती है। पुलिस प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम मिला था कि यदि छांगुर पीर पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बलरामपुर सहित पूरे प्रदेश में चक्का जाम, तालाबंदी और उग्र आंदोलन करेंगे।

बीस साल बाद एक हुए ठाकरे बंधु

● **संयुक्त रैली में उद्धव का दावा-हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं**

मुंबई। उद्धव ठाकरे गुट (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) की संयुक्त रैली में उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि वे साथ रहने के लिए साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने उनकी इस्तेमाल करो और फेंको नीति का कड़वा अनुभव लिया, अब हम उन्हें राजनीति से बाहर फेंकेंगे। मुंबई के वली डोम में आयोजित इस संयुक्त रैली में उद्धव ठाकरे ने मनसे के साथ यूबीटी के गठबंधन की घोषणा की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कई सालों बाद राज ठाकरे और वे एक साथ



सार्वजनिक मंच पर मिले। हम सभी ने उनकी उपलब्धियां देखी हैं। हर बार यह सवाल उठाया गया था कि क्या हम एक साथ आएंगे। अब हम साथ आए हैं, लोग हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा मिलन मराठी के लिए नहीं बल्कि नगर निगम के लिए है। हालांकि,

लेकिन हम हिंदी की अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री रहते हिंदी को अनिवार्य नहीं किया था। उद्धव ने कहा कि यदि आप मराठी लोगों के लिए न्याय की मांग करने वालों को गुंडे कहते हैं, तो हम गुंडे हैं।

उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि यदि आपको महाराष्ट्र में बालासाहेब ठाकरे का समर्थन नहीं होता तो क्या हमें हिंदुत्व सिखाने वाले सत्ता में होते? एकजुट होना जरूरी है जैसा कि हमने संयुक्त महाराष्ट्र समिति के दौरान किया था। उद्धव ठाकरे ने भाजपा के मराठी लोगों से भी एक साथ आने की अपील की। राज ठाकरे ने अपने भाषण में सत्तारूढ़ दल को कठोर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मराठी अभिमान में जरा भी कमी नहीं आई है। राज ठाकरे ने अपील करते हुए कहा कि मराठी एकता भविष्य में भी जारी रहनी चाहिए।

हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि मराठी के लिए साथ आए हैं। वे हमारे बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हम मराठी भाषा की पालकी के कहार बनेंगे और मराठी भाषा को पालकी में बिटाएंगे। हम किसी दूसरी भाषा के खिलाफ नहीं

मेडिकल शिक्षा तंत्र में हुए महाघोटाले की जांच कराए सरकार : कांग्रेस

एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में महाघोटाले का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता इसमें शामिल हैं और उनके कई मोहरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांग्रेस महासचिव रणदीपसिंह सुरजेवाला ने आज यहां एक बयान में कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण और इन कालेजों को मान्यता देने की पूरी प्रक्रिया में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला होने का खुलासा हुआ है। मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में हुए इस घोटाले के जरिए चूसखोरी से मेडिकल कॉलेज चलाने की अनुमति देने और इन कॉलेजों के माध्यम से मुन्नाभाई डॉक्टर

लेकिन हम हिंदी की अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री रहते हिंदी को अनिवार्य नहीं किया था। उद्धव ने कहा कि यदि आप मराठी लोगों के लिए न्याय की मांग करने वालों को गुंडे कहते हैं, तो हम गुंडे हैं।

उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि यदि आपको महाराष्ट्र में बालासाहेब ठाकरे का समर्थन नहीं होता तो क्या हमें हिंदुत्व सिखाने वाले सत्ता में होते? एकजुट होना जरूरी है जैसा कि हमने संयुक्त महाराष्ट्र समिति के दौरान किया था। उद्धव ठाकरे ने भाजपा के मराठी लोगों से भी एक साथ आने की अपील की। राज ठाकरे ने अपने भाषण में सत्तारूढ़ दल को कठोर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मराठी अभिमान में जरा भी कमी नहीं आई है। राज ठाकरे ने अपील करते हुए कहा कि मराठी एकता भविष्य में भी जारी रहनी चाहिए।

मेडिकल शिक्षा तंत्र में हुए महाघोटाले की जांच कराए सरकार : कांग्रेस

एजेंसी



नई दिल्ली। कांग्रेस ने मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में महाघोटाले का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता इसमें शामिल हैं और उनके कई मोहरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांग्रेस महासचिव रणदीपसिंह सुरजेवाला ने आज यहां एक बयान में कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण और इन कालेजों को मान्यता देने की पूरी प्रक्रिया में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला होने का खुलासा हुआ है। मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में हुए इस घोटाले के जरिए चूसखोरी से मेडिकल कॉलेज चलाने की अनुमति देने और इन कॉलेजों के माध्यम से मुन्नाभाई डॉक्टर

बनाने वाली प्रक्रिया का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष, कई मेडिकल कॉलेज और इसमें शामिल 36 मोहरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस प्राथमिकी में सुरेश सिंह भदोरिया भी शामिल हैं।



तैयार किया जाएगा, जो आगे मंडल और जिला स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। इससे आधुनिक तौर तरीकों का प्रसार तेजी से होगा और प्राकृतिक खेती को व्यापक रूप से अपनाया जाएगा।

राष्ट्रीय मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के तहत लोकल नेचुरल फार्मिंग इंस्टिट्यूशन किसानों को प्रशिक्षित

करने और उन्हें जागरूक बनाने में मदद करेगा। इससे प्राकृतिक खेती का आधार मजबूत होगा और किसान स्वावलंबी बनेंगे। योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें ब्रांड एंबेसडर

विचार/विमर्श

अब तक यह माना जाता रहा है कि कुछ बीमारियां वंशानुगत या यूं कहें कि आनुवांशिकी के कारण जन्मजात होती हैं। वह उम्र के साथ अपना असर दिखाना आरंभ कर देती हैं। नए शोध के अनुसार, बदलती जीवनशैली, रहन-सहन, आहार-विहार उससे भी गंभीर असर दिखाने लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार, जीन प्रभावित लोग बेहतर और संतुलित जीवनशैली से अपनी जीवन रेखा को बड़ा कर सकते हैं। चित्तजानक यह है कि बदलती जीवनशैली के कारण असामयिक मौत की संभावना 78 फीसदी तक अधिक हो गई है। नेचर मेडिसिन पत्रिका में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के आलेख में यह दावा किया गया है। शोधार्थियों ने यूके बॉयोबैंक से 5 लाख लोगों का आंकड़ा प्राप्त कर यह निष्कर्ष निकाला है। शोधार्थियों ने 164 फैक्टर और जेनेटिक जोखिमों का विस्तृत अध्ययन किया है। भारत भी इससे अछूता नहीं हैं। जीवनशैली और आहार-विहार में बदलाव के कारण ही आज हार्ट संबंधी रोग, कैंसर, डाइबिटिज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, डिप्रेशन और इसी तरह की कई बीमारियां आम होती जा रही हैं। इससे हर उम्र के लोग प्रभावित हैं। कल तक रईसों और उम्र के पड़ाव के अवसर पर होने वाली बीमारियां पूरी साम्यवादी सोच के साथ किसी को भी अपने दायरे में लेने लगी हैं। एक समय था जब सूर्योदय से पहले उठने और रात नौ-साढ़े नौ बजे तक सो जाने की सामान्य परंपरा रही है तो प्रातःकाल भ्रमण, दिन में भोजन के बाद कुछ समय के लिए आराम और रात को खाना खाने के बाद थोड़ी चहल कदमी रात को खाना खाने के बाद थोड़ी चहल कदमी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी मानी जाती थी। स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य सामग्री और खान-पान में संयम के साथ ही शुद्धता पर जोर दिया जाता था, जिससे शरीर को तदनुरूप पौष्टिक तत्व मिल सकें। आज हालात में तेजी से बदलाव आया है। रसोई और रसोई सामग्री की शुद्धता और गुणवत्ता की बात तो करना ही बेमानी होगा। मिलावट या फिर रासायनिक खाद-कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी आना तो स्वाभाविक ही है इसके साथ ही चंद लाभ के लिए खाद्य सामग्री में मिलावट आम होती जा रही है। इसके साथ ही प्रदूषित वातावरण बीमारियों का कारक तो बन ही रहा है इसके साथ ही दवाएं भी बेअसर होती जा रही हैं। एक शोध के अनुसार केवल धूम्रपान के कारण ही 21 तरह की बीमारियां जकड़ सकती हैं तो पारिवारिक

व रोजगारपरक तनाव के चलते 17 तरह की बीमारियां सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। खान-पान का बदलाव तो इसी से समझा जा सकता है कि जंक फूड या बाहर खाना खाना हमारी प्राथमिकता बनता जा रहा है। घर का खाना अब बच्चों की पंसद से दूर होता जा रहा है। रही सही कसर ऑनलाइन प्लेटफार्म ने पूरी कर दी है। आधी रात को भी गली मोहल्लों में स्त्रीगी या इसी तरह की संस्था से जुड़े कार्मिक को आसपास ही खाद्य सामग्री सप्लाई करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। जहां तक शुद्ध हवा और शुद्ध पानी का प्रश्न है तो आज आरओ और बोटलबंद पानी की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाये जाने लगे हैं। प्रदूषण के कारण शुद्ध हवा की बात करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। भले ही पार्कों में कितने ही घूम आओ या जिम में जाकर वर्कआउट कर आओ पर

सवाल यही है कि आपके आसपास शुद्ध हवा तो अब रही ही नहीं। वाहनों का प्रदूषित धुआं, ऐसी सहित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के कारण वातावरण का बढ़ता तापमान भी खतरनाक है। रही सही कसर मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है। पिता एक तरफ अपने मोबाइल में मशगूल है तो मां अलगा। बेटा-बहू अलग व बच्चों को भी इसी तरह से एक ही कमरे में बैठे होने के बावजूद एक दूसरे से अंजान की जैसी हालात में देखना आम है। सबसे खास यह कि सोशल मीडिया पर किस पोस्ट पर किसने लाइक किया या किसने इन्फोर किया यह तक तनाव का कारण बनता जा रहा है। सौ टके का सवाल यही है कि यदि हमें अपनी जीवन डोर लंबी करनी है तो समय रहते जीवनशैली और खान-पान में बदलाव करना होगा।

रील की दुनिया में रियल जिंदगी का विघटन, दिखावे की दौड़ में थकती जिंदगी

प्रियंका सौरभ

आज का समाज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां एक तरफ तकनीकी प्रगति ने जीवन को सहज और तेज बना दिया है, वहीं दूसरी ओर यही तकनीक धीरे-धीरे सामाजिक ताने-बाने को चुपचाप खोखला कर रही है। सोशल मीडिया, जो कभी सूचना और संपर्क का सशक्त माध्यम था, आज एक ऐसा नशा बन चुका है जिसने परिवार, संबंध और मानसिक स्वास्थ्य तीनों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पहले के समय में संवाद का अर्थ थाऽ बैठकर बात करना, साथ हंसना, रोना, बहस करना और समझना। आज यह सब कुछ ’टाइप’ और ’स्कॉल’ में बदल गया है। बच्चे हों या बुजुर्ग, महिलाएं हों या पुरुष सबके हाथ में स्मार्टफोन है और निगाहें स्क्रीन पर। कभी जो बातें रसोई, आंगन या बैठक में होती थीं, आज वो ’स्टेस अपडेट’, ’रील’ या ’पोस्ट’ में समा गई हैं। जिस रफ्तार से इंटरनेट की पहुँच और स्मार्टफोन का प्रसार हुआ है, उसी रफ्तार से हमारी असल दुनिया सिमटती जा रही है। सोशल मीडिया ने रिशतों की परिभाषा बदल दी है। अब दोस्त वो हैं जिनके पोस्ट पर हम हार्ट भेजते हैं, परिवार वो है जिसके मैसेज को हमने ’सीन’ किया हो, और सुख-दुख वो है जो हमने ’’स्टोरी’’ पर साझा किया हो। बच्चे अब खेल के मैदान में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर ’गेमिंग’ कर रहे हैं। स्कूलों से लौटकर मां-बाप से बात करने की बजाय वे इंस्टाग्राम खोलते हैं। किशोरावस्था, जो कभी आत्म-अन्वेषण और सामाजिक अनुभवों का समय हुआ करता था, आज वह सेल्फी, फिल्टर और वर्चुअल पहचान की दौड़ में उलझ गया है। सोशल मीडिया के इस अति-उपयोग ने एक ऐसा द्वंद्व पैदा किया है जहाँ व्यक्ति

दिखने में बहुत व्यस्त है पर भीतर से बेहद अकेला है। रिशते जो कभी जीवन का आधार होते थे, अब ’टैग’ और ’मेंशन’ में बदल चुके हैं। पति-पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन बातचीत क्याट्सपप पर होती है। मां-बाप बच्चों को खाना परोसते हैं और बच्चे खाने से पहले उसकी तस्वीर खींचकर पोस्ट करते हैं। यह आदत अब लत बन चुकी है। सुबह उठते ही सोशल मीडिया चेक करना, रात को सोने से पहले स्कॉल करना, हर क्षण को लाइव करना या कम से कम फोन में कैद करना। यह व्यवहार अब केवल समय की बर्बादी नहीं, बल्कि मानसिक विकारों का बीज भी बन चुका है। डिजिटल लाइफस्टाइल ने न केवल नींद, आहार, एकाग्रता को प्रभावित किया है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाला है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली ’परफेक्ट जिंदगी’ का निरंतर सामना आम इंसान को हीन भावना से भर देता है। दूसरों की सफलताओं, सुंदरताओं, यात्रा और जीवनशैली की तस्वीरें देखकर व्यक्ति अपने जीवन को तुच्छ समझने लगता है। यही वह क्षण होता है जब तनाव, अक्साद और आत्मग्लानि जैसे विकार जन्म लेने लगते हैं। खासकर किशोरों और युवाओं में यह प्रभाव और भी तीव्र है। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स ने आत्ममूल्यांकन का नया पैमाना बना दिया है। एक पोस्ट पर कम लाइक आए तो आत्म-सम्मान को ठेस लगती है, ट्रोलिंग हो जाए तो महीनों तक अक्साद की स्थिति बनी रहती है। दूसरी ओर, इस प्लेटफॉर्म पर ’फ़ेक आईडेंटिटी’ और ’वर्चुअल खैमेर’ का जाल इतना घना हो गया है कि लोग वास्तविकता से कटते जा रहे हैं। एक तरफ जहां व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए महंगे कपड़े, कारें और कैफ़े में फोटो पोस्ट करता है, वहीं असल जिंदगी में वह कर्ज और तनाव से ग्रि्त होता है। परिवारों में

संवाद की जगह अब संदेह, दूरी और झगड़े ने ले ली है। शादीशुदा जिंगियों में सोशल मीडिया पर गैजजरूरी बातचीत और अफ़ेयर्स ने तलाक के मामलों में वृद्धि की है। बच्चों में चिड़चिड़ापन, सोशल आइसोलेशन और एंकांतप्रियता बढ़ी है। बुजुर्ग अपने ही घर में उपेक्षित महसूस करते हैं क्योंकि बच्चे मोबाइल से खोए रहते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर झूठे आदर्शों और हानिकारक कंटेंट की भरमार भी है। लड़कियों को परफेक्ट फिगर के दबाव में डाला जाता है, युवाओं को सफलता के झूठे मॉडल दिखाकर भ्रमित किया जाता है, और छोटे बच्चे हिंसक या भ्रामक गेम्स में उलझ जाते हैं। आज जब हम ’फैक्ट चेकिंग’ और ’डिजिटल लिटरैसी’ की बात करते हैं, तब यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया सिर्फ सूचना या मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया हैऽ यह अब हमारी सोच, व्यवहार और संबंधों को गहराई से प्रभावित करने वाली शक्ति बन चुका है। भारत जैसे देश में, जहां संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, वहां सोशल मीडिया ने ’’संयुक्तता’’ की भावना को गहराई से चुनौती दी है। लोग अब त्योहारों में साथ बैठकर मिठाई खाने की बजाय उस मिठाई की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने में लगे रहते हैं। रिशतों का स्पर्श, संवाद की गर्माहट और एक-दूसरे की मौजूदगी की जो भावना होती थी, वह डिजिटल एल्गोरिद्म के पीछे छिप गई है। यह सच है कि सोशल मीडिया ने कई सकारात्मक चीजें भी दी हैंऽ आवाज उठाने का मंच, जामरुकता फैलाने का साधन और कई मामलों में न्याय की दिशा में जनबलाव बनाने का माध्यम लेकिन जब यही साधन साध्य बन जाए, तो समस्या खड़ी होती है। अब यह समय है जब हमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि हम सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता हैं, उसके

दास नहीं। तकनीक का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, न कि उसे निगल जाने के लिए। हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि लाइफ़ का मतलब लाइक्स नहीं होता। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि रील लाइफ़ से ज्यादा कीमती रियल लाइफ़ होती है। हमें खुद से पूछना होगा कि आखिरी बार जब हम अपने माता-पिता के पास बैठकर बिना मोबाइल के बात किए, वह कब था। समाधान यह नहीं कि सोशल मीडिया को छोड़ देना चाहिए बल्कि सोचना यह है कि इसे कैसे संतुलित किया जाए। हमें ’’डिजिटल डिटॉक्स’’ की आदत डालनी होगी। एक दिन बिना सोशल मीडिया के बिताना, भोजन करते समय मोबाइल को दूर रखना, रात को सोने से पहले स्क्रीन नहीं देखना, सुबह उठते ईश्वर या परिवार को याद करना, न कि इंस्टाग्राम को। सरकारों और संस्थानों को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। स्कूलों में डिजिटल संतुलन की शिक्षा, माता-पिता के लिए कार्यशालाएं और सोशल मीडिया कंपनियों पर बच्चों के लिए सुरक्षित सामग्री सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। मनुष्य का मस्तिष्क तकनीक से तेज है, लेकिन अगर वह तकनीक का गुलाम बन जाए, तो मानवता खो बैठता है। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली औजार है, बशर्ते हम उसे नियंत्रित करें, न कि वह हमें। अब समय है कि हम डिजिटल दुनिया में खुद को फिर से खोजेंऽ सच्चे रिशतों के लिए, मानसिक शांति के लिए और एक ऐसे समाज के लिए, जो तकनीक से सशक्त हो लेकिन संवेदनाओं से जुड़ा भी हो। सोशल मीडिया का यह नया नशा तभी टूटेगा जब हम आत्मनियंत्रण, संवाद और समझदारी से इसे अपनाएंगे। वरना यह नशा हमारे बच्चों से उनकी मासूमियत, हमारे परिवार से उसकी गर्माहट और हमारे समाज से उसकी आत्मा छीन लेगा।

कैब नियमन मानक

समय की जरूरत और नई पीढ़ी के रुझान के मद्देनजर पिछले कुछ वर्षों में देश में कैब सेवाओं का आधार व्यापक हुआ है। कैब सेवाएं उपलब्ध कराने वाली देशी-विदेशी कंपनियों की कड़ी प्रतिस्पर्धा ने इस क्षेत्र को आशातीत विस्तार दिया है। लेकिन साथ ही चालकों के हित संरक्षण और उपयोगकर्ताओं के हितों के नियमन की आवश्यकता भी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इन सवारी सेवाओं पर लागू होने वाले नये दिशा-निर्देशों का मकसद कैब एग्रीगेटर्स को अधिक अवसर प्रदान करना, ड्राइवरों के कल्याण को सुनिश्चित करना और उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाना है। सरकार ने उबर,ओला,इन-डाइव और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स को पीक ऑवर्स के दौरान बेस किराए से दुगना तक चार्ज करने की अनुमति दी है। उल्लेखनीय है कि पहले यह बेस किराए से डेढ़ गुना अधिक था। जिसे सेवाओं में दबाव की स्थिति में किराये की तेजी के रूप में दर्शाया जाता था। इसके साथ ही, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश-2025 में गैर-पीक ऑवर्स के शुल्क को बेस किराए से पचास प्रतिशत से कम नहीं रखा गया है। दरअसल, यह कदम ये सुनिश्चित करने के लिये है कि पीक ऑवर्स के दौरान यात्रियों पर बोझ न पड़े और एग्रीगेटर्स अन्य समय में भारी छूट के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को कम न करें। केंद्र सरकार के अनुसार, वर्ष 2020 के दिशा-निर्देशों के संशोधित संस्करण के नए मानदंड उपयोगकर्ता की सुरक्षा और चालक के कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देते हुए एक हल्की-फुल्की नियामक प्रणाली प्रदान करने का एक प्रयास है। इसमें शामिल अन्य प्रावधानों के अनुसार एग्रीगेटर्स को वाहन की लोकेशन और ट्रैकिंग डिवाइस लगानी होगी। इसका मकसद यात्रा करने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की है। ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें वाहन की स्थिति की जानकारी मिलती रहे। जिसका राज्य सरकारों के एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर से जुड़ा रहना भी जरूरी है। निश्चय ही यह महिला सवारियों की सुरक्षा के मद्देनजर अपरिहार्य कदम है। इसके अलावा ड्राइवरों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। उनके लिये बेहतर कमाई का प्रतिशत अनिवार्य किया गया है। उनके पास क्रमशः कम से कम पांच लाख और दस लाख रुपये का स्वस्थ और टर्म बीमा होना चाहिए। केंद्र सरकार के इस हालिया प्रयास ने राज्यों के लिये बाइक टैक्सियों को अनुमति देने का रास्ता भी खोल दिया है। निस्संदेह, ये प्रयास जहाँ अधिक राजस्व पैदा करने का जरिया बन सकता है, वहीं रोजगार सृजनकर्ता भी साबित हो सकता है। देश में जिस तरह बेरोजगारी की समस्या है, उसमें रोजगार के नये क्षेत्र पैदा करना वक्त की जरूरत है। यदि चालकों के लिये बेहतर कार्य परिस्थितियां और सामानजनक आय की व्यवस्था हो पाती है तो कई बेरोजगार इस दिशा में पहल कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि एग्रीगेटर चालकों के साथ मनमानी न कर सकें। हर छोटे-बड़े व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीविका उर्पाजन का अधिकार है। किसी भी काम को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। कई छात्र बेहतर कैरियर की चाह में अपनी पढ़ाई के खर्च के लिये पार्ट टाइम कार व बाइक टैक्सियां चलाते हैं। उन वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों को भी इनके साथ समानजनक ढंग से पेश आना चाहिए। उनके जीवन संर्षकों को हमें समझ देना चाहिए। नये प्रावधानों में राज्य सरकारों को सभी वाहनों, यहां तक कि ऑटो-रिक्शा और बाइक टैक्सियों के लिये भी आधार क्रियाय अधिसूचित करना होगा। उन्हें अगले तीन महीने के भीतर नये मानदंडों को अपनाने की सलाह दी गई है। निश्चित रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश-2025 मौजूदा वक्त की जरूरतों के अनुरूप ही हैं। जो एक और कैब चालकों के हितों की रक्षा करते हैं, वहीं यात्रा करने वालों की सुरक्षा व आर्थिक हितों की संरक्षण प्रदान करते हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नये प्रावधानों के नियमन के लिये कितनी पारदर्शी व्यवस्था बनायी जाती है। निश्चित रूप से कानून बनाने से महत्वपूर्ण यह भी है कि उनके क्रियान्वयन में सजगता व सतर्कता सुनिश्चित की जाए।

बारिश का कहर: प्रकृति की विक्षोभ या विकास की विफलता?

ललित गर्ग

बीते कुछ वर्षों में पहाड़ों में बारिश एवं बादल फटना अब डर, कहर और तबाही का पर्याय बन गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और पृ्वोत्तर के अन्य पहाड़ी राज्यों में हर वर्ष मानसून के साथ बहाव भूस्खलन, बादल फटना, पुल बहना और सड़कें टूटना एक आम दृश्य बन गया है। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थागत विफलता, सरकारी निर्माण की लापरवाही और अनियोजित विकास की पोल खोलने वाला यथार्थ है। निश्चय ही हाल के वर्षों में बारिश के पैटर्न में बदलाव आया है और बारिश की तीव्रता बढ़ी है। हर वर्ष जब मानसून की पहली बारिश पहाड़ों को भिगोती है, तो स्थानीय जनजीवन एक नई उम्मीद के साथ थि़ल उठता है। खेतों में हरियाली, नदियों में जल, और प्रकृति की शीतलता-मानसून एक उत्सव जैसा लगता है। लेकिन हालिया मानसूनी बारिश और मौसमी विक्षोभ की जुगलबंदी से हिमाचल के कई इलाकों में तबाही का जो भयावह मंजर उभरा, उसे हमें कुदरत के सबक के तौर पर देखना चाहिए। बड़ी संख्या में लोगों की मौत व लापता होने के साथ ही अज्ञेय रूपये की निजी व सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। 2023 और 2024 के मानसून ने हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जो कहर बरपाया, वह केवल आँकड़ों में सीमित नहीं है। दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों मकान जर्मींदोज़ हो गए, हजारों लोग बेघर हुए। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, सड़कों, सुरंगों और इमारतों के निर्माण ने जिस तरह से पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना के साथ छेड़छाड़ की, वह अब प्रकृति के प्रतिशोध का कारण बन रही है। उत्तराखंड में ‘ऑल वेदर रोड’, हिमाचल में सुरंगें और जल विद्युत परियोजनाएं-इन सभी ने विकास के नाम पर जिस प्रकार अंधाधुंध खुदाई और कटान किए हैं, उससे पर्वतीय क्षेत्र अपनी स्थायित्व खोते जा रहे हैं। वैज्ञानिक चेतावनियों के बावजूद कई निर्माण कार्यों में

2023 और 2024 के मानसून ने हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जो कहर बरपाया, वह केवल आँकड़ों में सीमित नहीं है। दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों मकान जर्मींदोज़ हो गए, हजारों लोग बेघर हुए। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, सड़कों, सुरंगों और इमारतों के निर्माण ने जिस तरह से पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना के साथ छेड़छाड़ की, वह अब प्रकृति के प्रतिशोध का कारण बन रही है। उत्तराखंड में ‘ऑल वेदर रोड’, हिमाचल में सुरंगें और जल विद्युत परियोजनाएं-इन सभी ने विकास के नाम पर जिस प्रकार अंधाधुंध खुदाई और कटान किए हैं, उससे पर्वतीय क्षेत्र अपनी स्थायित्व खोते जा रहे हैं।

भूगर्भीय सर्वेक्षण की अनदेखी की गई। नतीजा यह हुआ कि हल्की-सी भारी बारिश में ही सड़कें धंस जाती हैं, इमारतें दरकने लगती हैं, और पूरा गाँव मलबे में दब जाता है। वास्तव, पहाड़ी इलाकों में अतिवृष्टि से आपदा का जो भयावह मंजर उभर रहा है, उसके मूल में सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही मुख्य कारक नहीं है। दरअसल, इस तबाही के मूल में हमारी नाजुक हिमालयी पारिस्थिकीय तंत्र के प्रति बड़ी लापरवाही भी है। इस तथाकथित विकास के नाम पर हमने उस सीढ़ीनुमा रास्तों को दरकिनार कर दिया, जो पहाड़ों को मजबूती देते थे। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इनकी तीव्रता और आवृत्ति में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। इसकी मुख्य वजह हैं-अनियंत्रित पहाड़ों की कटिंग और खुदाई, बढ़ता भारी वाहन यातायात, जल निकासी की अव्यवस्था एवं वन क्षेत्र का अत्यधिक क्षरण। सरकारी निर्माण एजेंसियां अक्सर तय मानकों की अनदेखी करती हैं। निर्माण सामग्री घटिया होती है और मुनाफाखोरी के चक्कर में दियारें और पुल बरसात में ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) और पर्यावरण वैज्ञानिक लगातार चेताते रहे हैं कि हिमालयी क्षेत्र बेहद संवेदनशील हैं। फिर भी, निर्माण कार्यों के लिए भू-सर्वेक्षण, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) और जसनुवाई की प्रक्रियाओं को या तो टाल दिया

जाता है या खानापूर्ति भर की जाती है। चार धाम यात्रा मार्ग पर बनने वाली सड़क परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार रोका और सुझाव दिए कि पहाड़ों को काटने की बजाय टनल या वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे उलट है। निश्चय ही पूरी दुनिया में ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते मौसम के बिगड़े तेवर नजर आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में जल-प्रलय सी आपदा का विनाश निश्चय ही भयावह है। वैज्ञानिकों को इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि क्यों हुई है। इस साल की मानसूनी बारिश में मंडी जिले में बादल फटने की घटनाओं ने बुनियादी ढांचे, घरों, सड़कों और बगीचों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, उसने पहाड़ों में विकास के स्वरूप को लेकर फिर नये सिरे से बहस छेड़ दी है। राज्य के तमाम महत्वपूर्ण राजमार्ग भूस्खलन और अतिवृष्टि से बाधित रहे हैं। कांगड़ा घाटी में ऐतिहासिक रेल परिवहन को स्थगित करना पड़ा है। शिमला के पास एक बहुमंजिला इमारत के भरभरा कर गिरने के सोशल मीडिया पर वयरल वीडियो ने भयभीत किया। जब बारिश आती है, तो केवल इमारतें और सड़कें नहीं ढहतीं, आम लोगों का जीवन भी उजड़ जाता है। लोग रातोंरात बेघर हो जाते हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली-पानी की सुविधाएं बंद हो जाती हैं। प्रशासनिक अमला अकसर घटनास्थल पर देर से पहुंचता है और राहत कार्यों में राजनीतिक

रस्साकशी आड़े आ जाती है। राहत कैंपों में भोजन, शौचालय और दवाइयों की भारी कमी रहती है। जब किसी राज्य में बड़ी आपदा आती है, तभी मीडिया और नेताओं की नजर जाती है। हेलिकॉप्टर से निरीक्षण, मुआवज़े की घोषणाएं, और ‘हम साथ हैं’ जैसे बयान आते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम सामान्य होता है, पीड़ितों की सुध लेने वाला कोई नहीं रहता। लंबे समय तक पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य अथर में लटकते हैं। निश्चय ही मौसम के मिजाज में तल्खी नजर आ रही है लेकिन इस संकट के मूल में कहीं न कहीं एक-वैज्ञानिक विकास, खराब आपदा प्रबंधन और निर्माण में पारिस्थितिकीय ज्ञान की उपेक्षा भी निहित है। जिसने इस संकट को और अधिक बढ़ाया है। दरअसल, पानी के प्रवाह के जो प्राकृतिक तथ्य कहे, हमने उन पर बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर दी हैं। हमने अपेक्षाकृत नयी हिमालयी पर्वतमालाओं पर इतना भारी-भरकम विकास व निर्माण लाद दिया कि वे इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही हैं। निर्माण कार्य में स्थानीय पारंपरिक वास्तुकला और प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग बढ़ाया जाए। भू-सर्वेक्षण और ईआईए को अनिवार्य किया जाए, हर निर्माण से पहले वैज्ञानिक स्तर पर ज़मीनी की जाँच और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक हो। वनों की अंधाधुंध कटाई को रोक जाए और जलग्रहण क्षेत्रों को पुनर्स्थापित किया जाए। गाँवों और कस्बों के स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि निर्माण कार्य

ज़मीनी जरूरतों और जोखिमों के अनुसार हो। हिमालय को केवल भूगोल नहीं, अर्थात् का स्रोत भी माना जाता है। यहाँ की नदियाँ, पहाड़ और घाटियाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व रखती हैं। जब इन स्थानों पर अंधाधुंध निर्माण होता है, तो केवल भू-आकृति नहीं, सांस्कृतिक चेतना भी नष्ट होती है। पर्वतीय जीवन में तबाही के पीछे केवल प्रकृति नहीं, हमारी नीति, नियत और विकास का वह मॉडल जिम्मेदार है जो केवल तात्कालिक लाभ और मुनाफ़े पर केंद्रित है। हम पहाड़ों को केवल पर्यटक स्थल या परियोजना-स्थल की दृष्टि से न देखें, बल्कि वहाँ के पर्यावरण, संस्कृति और जीवन पद्धति को समझें और संरक्षण का दायित्व लें। नहीं तो हर बारिश के साथ पहाड़ों से जीवन खिसकता जाएगा और एक दिन यह संकट केवल स्थानीय न रहकर राष्ट्रीय बन जाएगा। दरअसल, पहाड़ों की संवेदनशीलता को देखते हुए नये सिरे से निर्माण के मानक तय करने होंगे। वहीं दैनिक जल निकासी और बरसाती पानी के प्रवाह के लिये वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था करनी होगी। निश्चित रूप से पहाड़ों में लगातार बढ़ती जनसंख्या और बुनियादी ढांचे में पहाड़ की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करने की कीमत हम चुका रहे हैं। भविष्य में ऐसी आपदाओं को टालने के लिये अतीत के सबक सीखकर हमें विकास के नये मानक तय करने होंगे। ऐसा लगता है कि किसी का इस पर ध्यान ही नहीं कि यदि बुनियादी ढांचे से जुड़े निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जैसा हादसा मंडी अथवा शिमला में हुआ, वैसे हादसों होते ही रहेंगे और उनका बोध प्रकृति पर मढ़कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाएगी। बात केवल हिमाचल की ही नहीं है, उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर भूस्खलन होने से तीर्थयात्री संकट में पड़े हैं। इसका कोई मतलब नहीं कि हम बार-बार विकसित भारत की बात करें, लेकिन सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की अनदेखी करें और मानक होते हुए भी उनका पालन न करें। इस तरह से तो हम विकसित देश नहीं बन सकते।

ख़ाद माफ़ियाओं पर चला प्रशासन का डंडा

- अवसर की आस लिए पहुंचे सैकड़ों लोग, विधवा महिला से लेकर पुजारी और व्यापारी तक ने रखी व्यथा

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

बांगरमऊ (उन्नाव)। स्थानीय तहसील सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार की उपस्थिति के चलते बड़ी संख्या में परियारी पहुंचे और अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। नगर के मोहल्ला पटेल नगर निवासी एक विधवा महिला ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि मोहल्ले के सभासद द्वारा प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत आवास दिलाने के लिए 2० हजार रुपये सुविधा शुल्क की मांग की गई। रुपये न दे पाने के कारण उसे अब



तक आवास नहीं मिला। इसी तरह, ग्राम मेला आलमशाह स्थित राम जानकी मंदिर के पुजारी बाबा रामखेलावन दास ने बताया कि मंदिर की लगभग पांच बीघा भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उस पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर झगड़े पर आमादा हो जाते हैं।

नगर के मोहल्ला कस्बा टोला निवासी वृद्धा सरला ने शिकायत करते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन बिना कारण बंद कर दी गई है, जिससे उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मिश्रा मार्केट स्थित कमलेश चंद्र, सुरेन्द्र गुप्ता, शशांक पटेल

व लक्ष्मी नारायण सहित अन्य व्यापारियों ने शिकायत में बताया कि उनकी दुकानों के सामने ई-रिक्शा और ऑटो को भरमार रहती है, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनती है और उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने मांग की कि इन वाहनों को संडीला मार्ग स्थित बस स्टैंड पर खड़ा किया जाए।

इस समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, एडीएम (राजस्व व वित्त) सुरशील कुमार, एसडीएम शुभम यादव, सीओ अरविंद कुमार, तहसीलदार साक्षी राय, प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत सिंह, बहेटा थाना प्रभारी मुन्ना कुमार, खंड विकास अधिकारी निशा सागर विश्वकर्मा,

समाधान दिवस में अधिकारियों की गैरहाजिरी पर एसडीएम सख्त
पुरवा (उन्नाव)। शनिवार को तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इस अवसर पर 79 फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखते हुए विभिन्न विभागों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं। एसडीएम और सीओ अजय कुमार सिंह ने शिकायतों को गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान 11 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। कार्यक्रम में राजस्व विभाग से 54, पुलिस विभाग से 12, विकास विभाग से 3, विद्युत विभाग से 3 और अन्य विभागों से 7 प्रकरण दर्ज किए गए। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग अपने उत्तरदायित्व का गंभीरतापूर्वक पालन करें। कार्यक्रम के दौरान कुछ विभागीय अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जिनके खिलाफ एसडीएम ने सख्त रुख अपनाया। सहायक विकास अधिकारी (सहकारी समिति) असोहा और पुरवा, अवर अभियंता विद्युत विभाग (पाटकपुर, मोरावां, पुरवा) तथा सहायक कृषि अधिकारी, पुरवा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन कार्य दिवस में स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस जारी होते ही संबंधित विभागों में हड़कंप मच गया। समाधान दिवस में जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों की अनुपस्थिति को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी संतोष श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार आशुतोष पांडेय, पुलिस, विद्युत, कृषि, आपूर्ति और अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप समाधान दिवस को केवल औपचारिकता न बनाकर प्रभावी बनाया जाएगा। अधिकारी समय से उपस्थित रहें और शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।

खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा तीन दिव्यांगों (दिनेश कुमार,



विनय कुमार सहित) को ट्राईसाइकिलें, किसानों (पंकज, बलीराम, केदारनाथ, बेचेलाल) को बीज किट और कन्या सुमंगला योजना के तहत अंबिका गुप्ता, बुशरा व वैष्णवी को सात-सात हजार

रुपये की धनराशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत काजल, सिमरन, सुनैना और शिवानी के अभिभावकों को ढाढ़-ढाढ़ हजार रुपये के चेक वितरित किए गए।

तहसील दिवस पर डीएम ने वितरित किया आयुष्मान कार्ड



राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

कौशाम्बी। चायल तहसील में आयोजित तहसील दिवस पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया। आयुष्मान भारत के जिला समन्वयक डा. ओम त्रिपाठी के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड तहसील दिवस में

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

उन्नाव। किसानों को समय पर उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। खरीफ सीजन में खाद की मांग के बीच प्रशासन नहीं चाहता कि कोई भी किसान कालाबाजारी, ओवररेटिंग या टैगिंग का शिकार हो। यही कारण है कि जिला कृषि अधिकारी श्री शशांक के नेतृत्व में जिलेभर में उर्वरक दुकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रशासन की इस सख्ती का असर साफ नजर आने लगा है। अब तक की गई कार्रवाई में 27 खाद विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस, 8 दुकानों के लाइसेंस निलंबित, जबकि 3 दुकानों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। यह अभियान किसानों को राहत और कालाबाजारी करने वालों को सीधा संदेश देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

खाद की कालाबाजारी, ओवररेटिंग और टैगिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं- जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विक्रेता खाद का वितरण केवल पीओएस मशीन के

संक्षिप्त समाचार

“एक पेड़ मां के नाम” अभियान का पुरवा में हुआ शुभारंभ

पुरवा (उन्नाव)। परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वृक्षारोपण अभियान “एक पेड़ मां के नाम” का शुभारंभ शनिवार को पुरवा कस्बे के श्रीमती राम रानी देवी चौरसिया पब्लिक स्कूल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (पीटीओ) शैफरफ किदवाई मैडम ने पौधा लगाकर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षकगण और विद्यालय प्रबंधन के सदस्य उपस्थित रहे। पीटीओ मैडम ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और पेड़ लगाने के साथ-साथ उन्हें बचाना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम लगाकर हम प्रकृति और भावनाओं को जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनना, सड़क पार करते समय सावधानी बरतना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन ने पीटीओ मैडम को अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम संयोजक स्वयंवर राजपुत ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य गौरव शर्मा सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं इस अवसर पर मौजूद रहे।।छात्र-छात्राओं ने भी पौधरोपण कर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का संकल्प लिया।

आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला व युवक की हुई मौत

बबेरू/बांदा। बबेरू कोतवाली क्षेत्र में भदेहदू व कुचेन्द्र गांव में अलग-अलग जगहों में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला और एक युवक की मौत हो गई, पहली घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भदेहदू गांव के मजरा सेम्मा पुरवा का है। जहां के लवलेश कुमार पुत्र कबीरदास 25 वर्ष के ऊपर खेतों में शुक्रवार को धान की बेड़ की रखवाली व मवेशियों को चराने के लिए गया था तभी देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के कुचेन्द्र गांव की है। जहां की रहने वाली महिला माया देवी पत्नी केशवबाबू उम्र 3० वर्ष की खेतों में बने झोपड़ी वाले घर में भी आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे महिला माया देवी की भी मौत हो गई है। जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई तो दोनों जगह के परिजनों ने आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू लेकर पहुंचे। जहां पर डॉक्टर द्वारा परीक्षण करने के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर पहुंची बबेरू कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह राजवत मय फोर्स व नायब तहसील मनोहर सिंह ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया है। वहीं मौत की खबर सुनकर उनकी परिवार जनों का रो-रोना बुरा होला है।

जल निकासी की समस्या को जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान

बांदा। गुल्वार को जिलाधिकारी बांदा श्रीमती जे. रिभा द्वारा मोहल्ला आजाद नगर (लोहिया पुल) में रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य के चलते उत्पन्न हुई जल निकासी की समस्या का गंभीरता से संज्ञान लिया गया। एडीएम राजेश वर्मा के साथ स्वयं मौके पर पहुंचकर उन्होंने स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तत्काल जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु ईओ नगर पालिका परिवद बांदा एवं रेलवे के अवर अभियंता को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शीघ्रता से कार्यवाही कर नागरिकों को राहत प्रदान की जाए।

नगर मजिस्ट्रेट ने जूस पिलाकर समाप्त कराया पीड़ित का अनशन

बांदा। नरैनी तहसील के ग्राम पंचायत पुकारी निवासी पीड़ित गणेश प्रसाद द्वारा अशोक स्तंभ पर चलाया जा रहा आमरण अनशन और चौथे दिन समाप्त हो गया। नगर मजिस्ट्रेट दे संदीप जे का जूस अनशन स्थल पर पहुंचकर गणेश प्रसाद को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया।गणेश प्रसाद ने बताया कि उनका पड़ोसी, ग्राम पुकारी का पूर्व प्रधान राजा उमरिया उर्फ रामबालक पुत्र काशी प्रसाद, पिछले काफी समय से अनिष्टकृत रूप से अपने घर का गंद पानी जबरन उनके आवासीय परिसर में निकाल रहा था। इस गंभीर समस्या को लेकर वह पिछले दो वर्षों से जिला एवं तहसील प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे, परंतु उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया।

आयुक्त ने तहसील दिवस में सहभागिता के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण

बांदा। आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा अजीत कुमार द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा के साथ जनपद हमीरपुर के मौदहा तहसील में आयोजित तहसील दिवस में प्रतिभाग किया गया। तहसील दिवस के दौरान प्राप्त शिकायतों का आयुक्त महोदय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायती प्रकरणों का तत्परता, समयबद्धता एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा उसकी आख्या आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) हमीरपुर को निर्देशित किया। इसके साथ ही आयुक्त ने आगामी वर्षा ऋतु के दृष्टिगत संभावित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारियों के तहत साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल, गौवश के लिए सुरक्षित ठहराव, स्वास्थ्य सेवाएं तथा विद्युत उपपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सुरेश खन्ना ने सांसद अरुण सागर के साथ ककरा न्यू सिटी कालोनी में किया वृक्षारोपण

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

शाहजहांपुर। शाहजहांपुर पहुंचे वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भाजपा सांसद अरुण सागर के साथ ककरा न्यू सिटी कालोनी में वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वनीकरण की कमी है। केंद्रीय करो में तत्परता, समयबद्धता एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग वृक्षारोपण करना होगा ।वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मां के नाम पेड़ लगाने की अपील की है। 9 जुलाई से शाहजहांपुर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नौ जुलाई से शाहजहांपुर में की वृक्षारोपण का विशेष अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि जितना कटान हुआ है। उम्मीद है उससे कहीं ज्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए। इसके कई फायदे होते हैं। वृक्ष हमको साया और फल भी देता और हरियाली का माहौल बनाता है। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से



अपील की है कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाओ। वित्त मंत्री ने जनपद वारिस्यों से अपील की है सुरक्षित और कवर्ड स्थान पर पेड़ लगाए और उसको जीवित रखने के लिए भी चिंता रखें। उन्होंने कहा कि मां के नाम से पेड़ जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि इसका एक फायदा और भी हो सकता है ।केंद्रीय करो में जो उत्तर प्रदेश को

हिस्सा मिलता है उसमें सबसे ज्यादा वीक प्वाइंट उत्तर प्रदेश वनीकरण नहीं है ।वनीकरण बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना होगा । ज्यादा वनीकरण करने से हम फाइनेंस कमीशन के समक्ष ज्यादा वित्त पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय करो में हिस्सा बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना होगा ।

सुरेश खन्ना ने सांसद अरुण सागर के साथ ककरा न्यू सिटी कालोनी में किया वृक्षारोपण

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

कर्नलगंज में सफाई व जलनिकासी व्यवस्था बढहाल, जिम्मेदार मौन

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क



का खतरा मंडरा रहा है। विभिन्न मोहल्लों में फॉगिंग मशीन से स्वाओं का छिड़काव भी नियमित नहीं होता, जिससे स्थिति और गंभीर हो रही है। धार्मिक त्योहारों और कार्यक्रमों के दौरान भी जिम्मेदार अधिकारी सफाई और नालियों की गंदगी निकासी पर ध्यान नहीं देते। जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता से नगरवासी आक्रोशित हैं। शासन और

गंभीर मरीजों के इलाज के लिए विधायक ने निधि से दिये लाखों

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

बांदा। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी क्षेत्र के गम्भीर बीमारियों से ग्रसित आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के इलाज के लिए बने एक सशक्त मददगार, मुख्यमंत्री राहत कोष से अपने ०8 वर्ष के कार्यकाल में स्वीकृत कराये 748.42 लाख व अपनी निधि से 1०3 लाख हैं। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए एक सशक्त सहारे के रूप में जनता के बीच में स्थापित हुये है। सदर विधायक द्वारा अपने ०8 वर्ष के कार्यकाल में अब तक अपने जनपद के आर्थिक रूप से कमजोर 424 रोगियों के इलाज हेतु प्रस्ताव भेजा, मुख्यमंत्री राहत कोष से माध्यम से 748.42 लाख रुपये स्वीकृत कराये गये है एवं विधायक निधि विकास योजना के अन्तर्गत बांदा सदर विधानसभा के 36 मरीजों के इलाज हेतु 1०3.०0 लाख रुपये निर्गत किये गये है।

प्रभारी यातायात की तत्परता से खोया बैग हुआ बरामद

बांदा। पुलिस अधीक्षक श्री पलाश बंसल के निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज,सीओ यातायात श्री राजीव प्रताप सिंह ,यातायात प्रभारी संजय मिश्रा के नेतृत्व में चलाए गए ई रिक्शा सत्यापन रजिस्ट्रेशन का जनता को मिल रहा है फायदा इसी फायदे के क्रम में आज हर्षिका पुत्री राम प्रकाश निवासी बबेरू जो एलएलबी 4जी ईयर की एकलव्य महाविद्यालय बांदा की छात्रा है कल पचेहर लगभग ३रू00 बजे मेडिकल कॉलेज से स्वरग कॉलोनी के लिए ई रिक्शा पर बैठी हुई थी स्वरग कॉलोनी पहुंचते ही उतर गई और ई रिक्शा पर रखा हुआ अपना बैग उठाना भूल गई। पर पहुंचने के बाद उसको अपने बैग की याद आई जब तक काफी देर हो गई थी। रिक्शा वाला भी ज्यादा से उतार कर जा चुका था काफी प्रयास करने के बाद नहीं मिला। रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद रिक्शा पर लगा हुआ 27 नंबर का टैग दिखाई दे रहा था। यातायात प्रभारी संजय मिश्रा को इसकी जानकारी दी गई यातायात प्रभारी के द्वारा रजिस्टर पर ई रिजस्टर्ड नाम पता एवं कोर्टेटेड नंबर के माध्यम से रिक्शा चालक से संपर्क किया गया उसने बताया यह बैग छूट गया था।

गैंगस्टर एक्ट मे तीन माफियाओं को कटोर कारावास की सजा और जर्माना

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

बांदा। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि जनपद के थाना अतर्रा के प्रभारी निरीक्षक भगवती प्रसाद मिश्रा ने 18 अप्रैल 2०17 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि टप्पू उर्फ दीपक उर्फ सुरेश निवासी थाना बाँदा रोड थाना अतर्रा जनपद बाँदा , राजकुमार ग्राम पंचोखर थाना अतर्रा जनपद बाँदा का एक संगठित गिरोह हैं जिनके विरुद्ध थाना अतर्रा में धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोगजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्ष्यों का साक्ष्य कायम प्रभावी पैरवी करके फलस्वरूप अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एडीजे चतुर्थ गैंगस्टर कोर्ट द्वारा अभिव्युक्त को ०2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500० /रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। गैंगस्टर की विवेचना निरीक्षक राम कैवल पटेल द्वारा संपादित की गई थी। जिस पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके

गैंगस्टर एक्ट मे तीन माफियाओं को कटोर कारावास की सजा और जर्माना

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

बांदा। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि जनपद के थाना अतर्रा के प्रभारी निरीक्षक भगवती प्रसाद मिश्रा ने 18 अप्रैल 2०17 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि टप्पू उर्फ दीपक उर्फ सुरेश निवासी थाना बाँदा रोड थाना अतर्रा जनपद बाँदा , राजकुमार ग्राम पंचोखर थाना अतर्रा जनपद बाँदा का एक संगठित गिरोह हैं जिनके विरुद्ध थाना अतर्रा में धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोगजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्ष्यों का साक्ष्य कायम प्रभावी पैरवी करके फलस्वरूप अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एडीजे चतुर्थ गैंगस्टर कोर्ट द्वारा अभिव्युक्त को ०2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500० /रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। गैंगस्टर की विवेचना निरीक्षक राम कैवल पटेल द्वारा संपादित की गई थी। जिस पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके

पैरोकार दिनेश कुमार कोर्ट मोहर्रर अमित राजपूत विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद अभियुक्त को सजा दिलायी गई। इनका एक संगठित गिरोह हैं जिसका गैंग लीडर टप्पू उर्फ सुरेश उर्फ दीपक हैं राजकुमार व राजेश सक्तिव सदस्य हैं यह गैंग अपने और अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए अवैध असलहा खाना व अपने गैंग के शौक पूरे करने के लिए चोरी करना, राहजनी,अवैध रूप से मोटर साईकिल चोरी करके सामान को बेचना ,जैसे अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करता है। गैंग लीडर व सभी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकद्दमे दर्ज है। यह सभी बहुत ही दुर्घात और बहुत ही शांति किस्म के अपराधी हैं। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने यह बताया की यह गैंग चोरी,राहजनी जैसे गंभीर अन्य अपराधो को निर्विचन निरीक्षक राम कैवल पटेल द्वारा संपादित की गई थी। जिस पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके

काउंसिलिंग, कानूनी पैरवी से संबंधित सहायता निशुल्क ली जा सकती है। यह पूरे भारत में चल रहा है। कहा कि अनारबाड़ी कार्यकर्ता सीधा समुदाय से जुड़ी रहती हैं। इसलिए उक्त नंबर को अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाएं ताकि पीड़िताओं को हर संभव मदद आसानी से मिल सके।

हेल्पलाइन के पंचे वितरित करके उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में लगाए के लिए कहा। शहरी बाल विकास परियोजना अधिकारी राम प्रकाश ने संभव अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शून्य से पांच वर्ष के बच्चों का वजन, लंबाई व ऊंचाई लेते हुए उनकी सूचना पोषण ट्रैकर एप पर फीड करेंगी। इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की (आरबीएसके) टीम अथवा नजदीक के सीएस्सी, पीएस्सी पर कराया जाएगा। चेहरा प्रमाणीकरण में लापरवाही बरतने वाली कार्यकर्ताओं को हिरावत देते हुए दो दिनों में यह कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

उत्तर रेलवे	
ई-ऑनलाइन सूचना	
वारेष्ठ कम्पल वाणिज्य प्रपक्ष, उत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई-ऑनलाइन प्रक्रिया किया जाता है।	
खसियन कूटि/खोन	Lucknow-MR-Division-Commercial/Northern Railway
नीतापी जूवी श.	CATERING-PRG-25
कार्य का विवरण	Minor catering unit under SML-BPL at Prayag Jn (PRG) Railway station ID PRG/PP-263/206/Adult at Platform No. 25
नीतापी जूवी प्रकलन तिथि	02.०7.2025
निर्गमि प्रारंभ तिथि (प्रारंभ जट)	17.०7.2025 at 1०:०० hrs.
नितापी बंद करने की तिथि व समय	17.०7.2025 at 1०:3० hrs.
विषयवस्तु विवरण जहाँ निम्नलिखित कीर्तियायाओं द्वारा नीतापी का पुन विवरण देखा जा सकता है : E-Auction Desk at www.bidspg.gov.in	
घासकाल की खेप में मुद्रकन को शास्य	2026/2025

शिकायतों का गुणवत्तापरक, समयबद्ध निस्तारण करें अफसर : जिलाधिकारी

डीएम ने फरियादियों की सुनी समस्याएं, लाभार्थियों को मिली स्वरोजगार की सौगात

- संपूर्ण समाधान दिवस में योजनाओं के लाभार्थियों को मिला सम्मान**

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखीमपुर खीरी। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील धौरहरा के सभागार में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, विधायक विनोद शंकर अवस्थी, एसपी संकल्प शर्मा और सीडीओ अभिषेक कुमार ने एक ओर जहां फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं, वहीं दूसरी ओर जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और किट सौंपे। मौके पर फैमिली आईडी अनुश्रवण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत सहायकों और कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। जनसुनवाई के दौरान डीएम व



एसपी ने अन्य अधिकारियों के साथ प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया और स्पष्ट निर्देश दिए कि जनशिकायतों की निष्पक्ष जांच कर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अधिकारियों से कहा कि शासन की प्राथमिकताओं में जनसमस्याओं का समाधान सर्वोपरि है। गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों की समस्याओं का

संबेदनशीलता से तुरंत समाधान करते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि शिकायतकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए संतोषजनक निस्तारण करें और भूमि विवादों में राजस्व-पुलिस की संयुक्त टीम तत्काल कार्यवाही करे। उन्होंने दो दृक कहा कि किसी भी स्तर की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इस समाधान

दिवस में कुल 82 शिकायती प्रार्थना पत्र पंजीकृत हुए, जिनमें से 06 का मौके पर निस्तारण किया गया। प्राप्त शिकायतों में राजस्व विभाग की 26, पुलिस विभाग की 22, विकास विभाग की 06,चकबंदी की 13, समाज कल्याण विभाग की 04, नगर निकाय की 02, आपूर्ति विभाग की 03, अन्य विभाग की 06 शिकायतें शामिल रहीं। सभी प्रार्थना पत्रों को पृष्ठांकित कर संबंधित विभागों को शीघ्र निस्तारण हेतु सौंपा गया। इस दौरान एसडीएम शशि कंत मणि, सीओ शमसेर बहादुर सिंह, पीडी एसएन चौरसिया, डीडीओ गजेन्द्र प्रताप सिंह, तहसीलदार आदित्य विशाल सहित जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जरूरतमंदों को मिला लाभ, कर्मठों को सम्मान

संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, विधायक

संपूर्ण समाधान दिवस में 50 शिकायतों में सिर्फ 6 का मौके पर निस्तारण

गोला गोकर्णनाथ खीरी। तहसील गोला में उपजिलाधिकारी युग्रांतर त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सभागार में संपन्न हुआ। समाधान दिवस में कुल पचास फरियादी शिकायत लेकर आए जिसमें से सिर्फ छः शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण हो सका , शेष 44 फरियादियों की शिकायतें सम्बंधित अधिकारियों को सौंप दी गईं। शिकायतों में सबसे ज्यादा चौबीस शिकायत राास्त्व एवं आपदा विभाग, संयुक्त जांच हेतु की छः शिकायतें, पुलिस विभाग की त्र्यारह, ग्राम विकास विभाग की दो, खाद एवं रसद विभाग की चार, विधुत विभाग की दो,नगर विकास विभाग की एक, शिकायतें प्राप्त हुईं , जिनमें से राजस्व विभाग की छः शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण हो सका। इस समाधान दिवस में तहसीलदार गोला भीम चंद ,पुलिस क्षेत्राधिकारी गेवन्द्र पाल गौतमनाथ, तहसीलदार सर्वेश यादव, भानू प्रताप सिंह व अन्य विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

लखीमपुर खीरी। कांग्रेस की नव नियुक्त जिला व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का स्वागत व शपथ ग्रहण कार्यक्रम लखीमपुर शहर के बिलोबी हाल में आयोजित किया गया
द्य जिला व ब्लॉक कांग्रेस की कमेटी में सभी जातियों,वर्गों को कांग्रेस पार्टी की मंशा और संकल्प के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है द्य पूरे प्रदेश में संगठन सृजन अभियान पूरे जोर-शोर से चल रहा है। जिला/शहर कार्यकारिणी के गठित होते ही संगठन सृजन अभियान का पहला चरण पूर्ण हो चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से हुई द्य तत्पश्चात सभी पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों और दायित्वों की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सतीश अजमाजी ने कहा `` ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। जहां एक ही मंच पर जिला/शहर कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों को

शारदा नदी द्वारा हो रहे कटान स्थल पर पहुंचे खीरी : सांसद उत्कर्ष वर्मा

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

पलियाकला खीरी। अतरिया रेलवे क्रॉसिंग के पास शारदा नदी द्वारा हो रहे कटान स्थल पर पहुंचे खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा कटान पर कार सेवा कर रहे हैं लोगों से बातचीत करते हुए सांसद उत्कर्ष वर्मा ने कहा कि शारदा नदी में हुए चैनैलाइजेशन कार्य योजना विफल रही। अगर चैनैलाइजेशन का कार्य सही तरीके से हो गया होता तो शायद यह नौबत नहीं आती।

चैनैलाइजेशन कार्य योजना की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि खनन नहीं होना चाहिए वहीं दूसरी तरफ शारदा नदी में पिछले कई वर्षों से बहुत जोरों पर खनन हुआ जिसका खामियाजा पलिया विधानसभा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हर साल आने वाली बाढ़ के लिए सरकार के पास कोई स्थाई योजना नहीं है। बाढ़ की समस्या को लेकर जनता में काफी आक्रोश है। पलिया क्षेत्र में जब भी कोई आपदा आई है तो बाबा गुरनाम सिंह महंगापुर वाले क्षेत्र की जनता के साथ खड़े नजर आए हैं।



पलिया क्षेत्र की जनता उनके सहयोग के लिए हमेशा आभारी रहेगी। आज भी जो रेलवे लाइन पर कटान रोकने का कार्य चल रहा है हुआ भी बाबा जी की अपील पर चल रहा है।

अगर यह कार्य प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया जाता तो अब तक रेलवे लाइन कितनी कट गई होती इसकी

कल्पना भी नहीं की जा सकती।इस मौके पर विधानसभा प्रभारी प्रीतेन्द्र सिंह कक्कू सांसद प्रतिनिधि अशोक वर्मा जिला उपाध्यक्ष रोहित वर्मा गुरप्रिंह सिंह नन्नर अमरजीत सिंह सोढ़ी तरसेम सिंह सतनाम सिंह भाटी अशोक गुप्ता सुरेश वर्मा मोहन शर्मा तेजिंदर सिंह कुलवंत सिंह देवेन्द्र सिंह निक्कू आदि मौजूद रहे।

कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का स्वागत व शपथ ग्रहण का हुआ आयोजन



संकल्प दिलाया जाये कि आज भाजपा शासनकाल में जिस तरह से समाज में नफरत फैलाई जा रही है,। संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे दौर में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और गांधीवादी सिद्धान्तों को अपनाकर हम लड़ेंगे और देश में पुनः शांति,सद्भाव और प्रेम की स्थापना करेंगे । इस अवसर पर जिला फ़ंटल व प्रकोष्ठ प्रभारी श्री उमा शंकर पांडे ने कहा `` हम संकल्पित हैं कि आगामी 15 अगस्त ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। जहां एक ही मंच पर जिला/शहर कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों को

जंगल से निकले हाथियों के झुंड ने रौंदी किसानों की फसल



राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

पलियाकलां खीरी। दुधवा जंगल से निकलकर जंगली हाथियों का झुंड किसानों के खेतों में पहुंचा और किसानों के खेतों में खड़ी गन्ने की फसल को अपने पैरों तले रौंदकर बर्बाद कर दिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग आबादी की ओर आ जाते हैं। कभी शिकारी जानवर ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर देता है तो कभी उनके पशुओं को मौत के घाट उतार देता है। इतना ही नहीं बाघ तो

कई ग्रामीणों की जान भी ले चुके हैं। इसके साथ ही जंगली हाथियों का झुंड किसानों को अपने पैरों तले रौंदकर फसलों को अपने पैरों तले रौंदकर नष्ट कर दिया। ग्रामीण मैकू के खेत में भी हाथियों ने उत्पात मचाकर फसलों व पौधों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों की चिंहाड़ सुनते ही आस पड़ोस के अन्य लोग बाहर निकले और गोले ट्रैक्टर आदि का सहारा लेकर कुछ भगाने में कामयाबी हासिल कर सके।

भीरा में वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत निकाली गई जागरूकता रैली



पलियाकलां खीरी। भीरा में पौधरोपण महा अभियान एक पेड़ मां के नाम वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली के साथ पौधरोपण किया गया। शनिवार को भीरा वन विभाग द्वारा छाजू राम केन ग्रोवर्स इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय भीरा प्रथम व विवेकानंद एकेडमी के छात्रों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। वन विभाग द्वारा विद्यालय में पौधरोपण करने के साथ-साथ छात्रों को घर में लगाने के लिए पौधे भी दिए गए। इस दौरान छाजू राम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मुकुट बिहारी मिश्रा, विवेकानंद एकेडमी के शिक्षक नेरन्द्र चंद जोशी, प्राथमिक विद्यालय भीरा प्रथम की प्रधानाध्यापिका सीमा अग्रवाल, स्फूर्ति दीक्षित, भीरा रेंजर विनय कुमार, डिप्टी रेंजर अखिलेश शर्मा सहित छात्र छात्राएं विद्यालय स्टॉफ एवं वन विभाग स्टॉफ मौजूद रहे।

सरकारी वाहन न होने से अजान चौकी में गश्त प्रभावित, अपराध बढ़ने की आशंका

- बाघ की रहल कदमी के चलते पुलिसकर्मियों को बाइक से रात्रि गस्त से हो सफ़ता है खतरा**

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

अजान खीरी। थाना हैदराबाद अंतर्गत पुलिस चौकी अजान इन दिनों संसाधनों के अभाव से जूझ रही है। चौकी में सरकारी जिप्सी वाहन न होने की वजह से पुलिस गश्त (पेट्रोलिंग) बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसका सीधा असर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, गश्त न होने के कारण क्षेत्र में चोरी, मारपीट और छोटे-मोटे विवाद की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। आपराधिक घटनाओं के दौरान पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंच पा रही, जिससे लोगों में असंतोष और भय का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, अजान चौकी में पहले एक पुरानी सरकारी जिप्सी थी, जिसे वाहन

बाइक सवार दो लोग भैंस से टकराए, एक की मौत दूसरा घायल

बबेरू/बांदा। कमासिन थाना क्षेत्र के कठार व कल्लूपुर गांव के बीच बाइक सवार दो लोग की भैंस से टक्कर हो गई, बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं दूसरा घायल हो गया। कमासिन थाना क्षेत्र के पछौहा गांव के रहने वाले संजय पुत्र होरीलाल उम्र 28 वर्ष से यह अपने रिश्तेदार शोभा पुत्र भोला उम्र 50 वर्ष, निवासी बबेरू यह एक ही बाइक में सवार होकर शुक्रवार की शाम दोनों लोग फतेहपुर जनपद के पहाड़पुर से बाइक में सवार होकर पछौहा गांव जा रहे थे। तभी कल्लूपुर व कठार गांव के बीचो-बीच अचानक बाइक के सामने भैंस आ गई। जिससे बाइक चालक ने ब्रेक लिया, तभी तुरंत अनियंत्रित होकर सीधा बाइक भैंसे से टकरा गई। जिसमें दोनों व्यक्ति रोड में गिर पड़े, राहगीरों के द्वारा पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एंबुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन भेजा गया।



की जर्जर स्थिति के चलते कुछ समय पूर्व लखीमपुर पुलिस लाइन में भेज दिया गया। नई गाड़ी अब तक चौकी को नहीं मिली है। ऐसे में पुलिसकर्मि निजी वाहनों और मोटरसाइकिलों के सहारे गश्त करने को मजबूर हैं। मोटरसाइकिल से गस्त करने पर शेरों का खतरा बना रहता है। वहीं चौकी क्षेत्र में पिछले काफी समय से खूंखार बाघों की मौजूदगी ने मौजूदा पुलिस कर्मियों को बाइक से रात्रि गस्त करना खतरं से खाली नहीं होगा, ज्ञात हो कि बाघ के हमले में दो किसानों की जाने जा चुकी है।ये शावकों सहित पकड़ी गई एक बाघिन के आलावा और भी वन्य जीवों

बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों पर बनी सहमति नगर पालिका में बोर्ड बैठक का आयोजन



राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क

पलियाकलां खीरी। नगर पालिका सभागार में चेयरमैन लक्ष्मी देवी गुप्ता और ईओ की मौजूदगी में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड बैठक में शामिल प्रस्तावों ने नगर के विकास को लेकर कई प्रस्ताव रखे जिन पर विचार-विमर्श के बाद सहमति जताई गई। शनिवार को नगर पालिका सभागार में बोर्ड बैठक पालिकाध्यक्ष लक्ष्मी देवी गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में अधिशासी अधिकारी विजय बहादुर यादव भी मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कराया मृतक गौवंश का अंतिम संस्कार

गोला गोकर्णनाथ खीरी। गोला नगर के सिकंदराबाद रोड पर ग्राम अलियापुर के पास एक मृतक गौवंश के पड़े होने की जानकारी राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष राकेश कर्नौजिया को प्राप्त हुई। जिला अध्यक्ष राकेश कर्नौजिया ने अपने संगठन के कार्यकर्ताओ को घटनाग्रस्त जगह पर भेजकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से जेसीबी भेजकर जिला उपाध्यक्ष अनुज वर्मा,गगन कुमार,शिवम श्रीवास्तव,अमन कुमार ,अशिश कुमार व पुलिस की मौजूदगी में मृतक गौवंश का अंतिम संस्कार किया गया।

पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार
गोला गोकर्णनाथ खीरी। पुलिस अधीक्षक खीरी के आदेशानुसार वाछित/वारण्टी अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत गोला पुलिस टीम द्वा़र दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्र0 नि0 अम्बर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया शनिवार को वारण्टी अधि0 जमुना प्रसाद पुत्र छोटेलाल नि0 ग्राम भैठिया थाना गोला से वारन्ट दिखाकर पुलिस ने हिरासत में लिया गया । धारा 26 एफ0 एक्ट का वारण्टी अधि0 रामविलास पुत्र इतवारी नि0 ग्राम नाथपुर थाना गोला को उसके घर से वारन्ट दिखाकर हिरासत में पुलिस ने लिया गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

पलिया के मोबाइल दुकानदार को ले गई जयपुर पुलिस
पलियाकलां खीरी। राजस्थान के जयपुर जिले में मोबाइल लूट की घटना में शामिल एक मोबाइल पलिया के एक दुकानदार के पास से बरामद हुआ है। जयपुर पुलिस दुकानदार को पृछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। जयपुर के मणिपुर थाने में लगभग डेढ़ महीना पहले एक भाजपा नेता के पीए के घर पर लूट हुई थी। लूट की इस घटना में कई मोबाइल भी लूटे गए थे। उनमें से एक मोबाइल पलिया पुलिस चौकी के पीछे एक दुकानदार के पास से बरामद हुआ है। राजस्थान पुलिस ने सर्विलांस के जरिए मोबाइल को ट्रेस किया और उसके बाद आरोपित को पकड़ने के लिए गुरुवार को पलिया पहुंच गई। जयपुर पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से निखिल गुप्ता को उसके मोबाइल साथ से पकड़ा और पृछताछ के लिए अपने साथ जयपुर ले गई। पुलिस के मुताबिक जो मोबाइल बरामद किया गया है वह मोबाइल जयपुर में दो जगह बिका था और उसके बाद उसे सीतापुर के एक व्यक्ति ने खरीव और अब वह निखिल के पास था। जयपुर पुलिस ने मोबाइल बरामद करने के बाद उसकी पूरी लोकेशन बांदा थी कि वह कब कब कहां पर उपयोग किया गया। मोबाइल के साथ दुकान मालिक को भी जयपुर पुलिस साथ लेकर वापस चली गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि जयपुर पुलिस आई थी। लूटा गया एक मोबाइल पुलिस चौकी के पीछे स्थित एक मोबाइल की दुकान से बरामद हुआ है। पलिया पुलिस भी उनके साथ गई थी और दुकान मालिक व मोबाइल के साथ चौकी पर लेकर आए थे। उसके बाद आरोपित को लेकर जयपुर चले गए हैं।

हैदराबाद थाना पीस कमेटी बैठक से पत्रकार नदारद, संवादहीनता पर उठे सवाल
अजान खीरी। मोहरंरा जैसे संवेदनशील पर्व के मद्देनजर हैदराबाद थाना परिसर में शांति समिति ''पीस कमेटी'', की बैठक बुलाई गई, परंतु इस महत्वपूर्ण बैठक में स्थानीय पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किया गया। इस रविये ने थाना प्रशासन और मीडिया के बीच संवादहीनता को उजागर कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, थाना स्तर पर आयोजित होने वाली पीस कमेटी की बैठकें क्षेत्रीय सौहार्द और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद अहम होती हैं। इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, समाजसेवियों और मीडिया की मौजूदगी अपेक्षित रहती है। ऐसे में पत्रकारों की अनुपस्थिति ने न केवल पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पुलिस-मीडिया संबंधों की स्थिति को भी कष्टघरे में ला खड़ा किया है। विशेष रूप से तब, जब पुलिस विभाग अक्सर अपने ''गुडवर्क'' यानी उपलब्धियों को प्रमुखता से मीडिया में प्रचारित करने के लिए प्रेस नोट्स और वार्ताएं आयोजित करता है।

मुझे चुनौतियां पसंद हैं, मुझे जिम्मेदारी पसंद है : सिराज

एजेंसी

बर्मिंघम। घर के बाहर जब भी मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह के बिना उतरते हैं तो उनमें एक अलग ही निखार देखने को मिलता है या यूँ कहें वह एक अलग ही तरह से जिम्मेदारी लेते दिखते हैं। एजबस्टन में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन शुक्रवार को सिराज ने अपने टेस्ट करियर में तीसरी बार पारी में पांच या उससे अधिक विकेट लिए। मैच के बाद सिराज ने कहा कि जब भी चुनौती आती है तो उनको वह पसंद आती है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में भी काफी चुनौतियां झेली हैं। सिराज ने मैच के बाद जियो हॉटस्टर पर दीप दासगुप्ता से बातचीत में कहा, “हां, बिल्कुल जब आपके साथ आकाश दीप हो जो तीन-चार टेस्ट ही खेला हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो जो



दो-तीन मैच ही खेला हो, तो मेरे 38 मैच हो गए हैं, तो मैं जिम्मेदारी ले रहा था। मेरा भी मन करता है कि बोर्ड पर 600 रन हैं तो मैं कुछ अलग करूं, मेरा बस यही था कि दबाव बनाकर रखूं, अगर मुझे विकेट नहीं मिल रहा है तो जो मेरे साथ गेंदबाजी कर रहा है उसको विकेट मिले। घर के बाहर बुमराह के साथ खेलने पर सिराज की

औसत 32.4 की है लेकिन जब वह बुमराह के बर्ना उतरते हैं तो औसत 23.3 की हो जाती है। यानि बुमराह के बिना वह ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा, “ये तो केवल आंकड़े” है लेकिन मुझे चुनौतियां पसंद हैं, जहां से मैं आता हूं मैंने ज़िंदगी में काफी चुनौतियां झेली हैं, वहां से उबरकर आया हूं, तो

मुझे चुनौतियां पसंद हैं। सिराज के लिए इंग्लैंड में यह पहली बार पारी में पांच विकेट हैं, इससे पहले वह दो बार एक विकेट से यह कामयाबी हासिल करने से चूक गए थे। लेकिन सिराज इस मुकाम को हासिल करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सिराज ने कहा, “मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था, गेंदबाजी अच्छी कर रहा था लेकिन पांच विकेट नहीं मिल पा रहे थे। लॉर्ड्स में भी चार विकेट थे, यहां पर भी पहले चार विकेट मेरे नाम थे। अब अच्छा लग रहा है। विकेट धीमा था और जिम्मेदारी मेरे पास थी। मैं बस एक ही जगह पर गेंद करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी ओर से अधिक कुछ नहीं करने का प्रयास कर रहा था। इससे टीम में भी आत्मविश्वास आता है और माहौल भी बदल जाता है।

सबालेंका ने स्थानीय दावेदार राडुकानु को दी शिकस्त

लंदन। शीर्ष रैंकिंग वाली एरीना सबालेंका ने विम्बलडन में स्थानीय दावेदार एम्मा राडुकानु के शानदार सफर को विम्बलडन में 7-6(6) 6-4 की जीत के साथ रोक दिया। ऑल इंग्लैंड क्लब में दो बार की सेमीफाइनलिस्ट सबालेंका ने शुक्रवार रात को दोनों सेटों में 2021 यूएस ओपन चैंपियन के खिलाफ जोरदार वापसी की। राडुकानु 18 साल की उम्र में यूएस ओपन में एक क्वालीफायर के रूप में अपने खिताब के बाद से अपना सर्वश्रेष्ठ टेनिस खेल रही थीं। राडुकानु 74 मिनट के पहले सेट में एक समय 4-2 से आगे थी लेकिन सबालेंका ने अगले 12 में से 11 अंक हासिल कर 5-4 की बढ़त बना ली। राडुकानु इसके बाद टाईब्रेकर में भी 6-5 से आगे थी लेकिन सबालेंका ने शानदार वापसी कर अंतिम तीन अंक को जीत कर बहुत कायम की। तीन बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सबालेंका ने इसके बाद दूसरे सेट में ब्रिटेन की खिलाड़ी को ज्यादा मौके नहीं दिये। सबालेंका पिछले लगातार तीन ग्रैंड स्लेम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचीं, जिसमें उन्होंने पिछले साल सितंबर में यूएस ओपन जीता था।

श्रीकांत शीर्ष वरीयता प्राप्त चोऊ टिएन चेन को हराकर कनाडा ओपन के सेमीफाइनल में

एजेंसी

कैलगरी। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखते हुए यहां कनाडा ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में चीनी ताइपे के शीर्ष वरीय चोऊ टिएन चेन पर सीधे गेम में जीत दर्ज करके पुरुष एकल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विश्व चैंपियनशिप के पूर्व रजत पदक विजेता और इस साल मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में पहुंचने वाले श्रीकांत ने शुक्रवार रात को 43 मिनट तक चले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विश्व के छठे नंबर के खिलाड़ी चेन को 21-18, 21-9 से हराया। वर्तमान में विश्व में 49वें स्थान पर काबिज श्रीकांत का फाइनल में जगह बनाने के लिए अब जापान के तीसरे वरीय केंटा निशिमोटो से मुकाबला होगा। इससे पहले 2022 विश्व जूनियर चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता



एस शंकर मुथुसामी सुब्रह्मण्यम ने 79 मिनट तक चले क्वार्टर फाइनल में निशिमोटो से 15-21 21-5 17-21 से हारने से पहले उनके सामने कड़ी चुनौती पेश की। पहिला एकल में श्रीयांशी वलिसेट्टी का प्रभावशाली प्रदर्शन डेनमार्क की अमाली शुल्ज से हारने के बाद समाप्त हो गया। श्रीकांत ने चेन के खिलाफ शानदार शुरुआत करते हुए 5-0 की बढ़त हासिल की

लेकिन चीनी ताइपे के खिलाड़ी ने वापसी करके स्कोर 16-16 से बराबर कर दिया। श्रीकांत ने हालांकि अगले छह में से पांच अंक लेकर गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में श्रीकांत ने इंटरवल तक 11-6 की बढ़त बना ली और इसके बाद भी अपना दबदबा कायम रखते हुए 19-7 की बढ़त बनाकर मैच आसानी से अपने नाम कर लिया।

दीप्ति शर्मा बनीं महिला टी 20 आई में संयुक्त रूप से दूसरी सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज

एजेंसी

नई दिल्ली। लंदन के द ओवल में शुक्रवार को इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ खेले गए तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने करियर का 144वां विकेट लेकर महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय में संयुक्त रूप से दूसरी सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की पूर्व कप्तान निदा डार की बराबरी भी कर ली। महिला टी20आई में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की पूर्व तेज गेंदबाज मेगन शट के नाम है, जिन्होंने 151 विकेट लिए हैं। दीप्ति शर्मा महिला टी20आई में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज भी हैं। अब उनके बाद राधा यादव इस सूची में शामिल



होने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज बन गई हैं, जिन्होंने इस मैच में इंग्लैंड की स्टैंड-इन कप्तान टैमी ब्यूमोंट को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की। 27 वर्षीय दीप्ति ने जनवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20आई डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने अपने पहले चार ओवर के स्पेल में 19 रन देकर एक विकेट लिया था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4 विकेट पर 10 रन है, जो उन्होंने नवंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हासिल किया था।

महिला क्रिकेट : तीसरे टी20 में अंतिम गेंद पर जीता इंग्लैंड, भारत को सीरीज जीतने से रोका

एजेंसी

लंदन। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे टी20 में भारत को रोमांचक अंतिम गेंद वाले मुकाबले में 5 रन से हराकर सीरीज में पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मेज़बान टीम ने पांच मैचों की टी20 श्रृंखला में अपना ख़ाता खोला।

इस मुक़ाबले में इंग्लैंड की गेंदबाजी की कप्तान सोफी एक्लेस्टोन और लॉरेन फ़ाइलर ने संभाली। एक्लेस्टोन ने जहाँ किफायती गेंदबाजी की, वहीं फ़ाइलर ने अहम मौकों पर विकेट निकालकर भारत को जीत से दूर रखा। 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शानदार शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (56 रन, 49 गेंद) और शेफाली वर्मा (47 रन, 25 गेंद) ने एक ओर अर्धशतकीय साझेदारी की। शेफाली अर्धशतक से चूक गई, उन्हें



एक्लेस्टोन ने पवेलियन भेजा। तीसरे नंबर पर उतरी जेमिमा रोड्रिग्स (20 रन, 15 गेंद) पिछले मैच में अर्धशतक जमाने के बाद अच्छे फॉर्म में दिख रही थीं, लेकिन फ़ाइलर ने स्मृति के बाद उन्हें भी जल्द आउट कर भारत की उम्मीदों को झटका

नवीन ऊर्जा, एआई अवसरंचना से रिलायंस का बाजार मूल्य 50 अरब डॉलर बढ़ेगा

नयी दिल्ली। नवीन ऊर्जा और कृत्रिम मेधा (एआई) बुनियादी ढांचे में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निवेश से कंपनी के बाजार मूल्य में अनुमानित 50 अरब डॉलर की वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। अरबपति मुकेश अंबानी द्वारा संचालित तेल से लेकर दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र की यह कंपनी महमूद सुजन के अपने अगले चरण के लिए कमर कस रही है। वर्तमान में 240 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की रिलायंस की भविष्य की वृद्धि इसके विविध कार्यक्षेत्रों, विशेष रूप से नवीन ऊर्जा और एआई के विस्तार पर निर्भर करती है। सुजन से जुड़ी (जेन) एआई रिलायंस के लिए अगला मोर्चा है क्योंकि यह जामनगर ऊर्जा परिसर को अपने ऊर्जा उत्पादन का मॉड्रिकरण करने के लिए फिर से तैयार कर रहा है, जो जनरल एआई रैंप के लिए वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख बाधा है।

पाकिस्तान, अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता का महत्वपूर्ण दौर संपन्न

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान और अमेरिका ने व्यापार वार्ता का महत्वपूर्ण दौर पूरा कर लिया है। शनिवार को समाचार पत्र ‘डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के साथ पाकिस्तान की एक ऐसे समझौते पर सहमति बन गई है जो उसके प्रमुख निर्यात क्षेत्रों के भविष्य को आकार दे सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए हैं, लेकिन औपचारिक घोषणा तभी होने की उम्मीद है जब अमेरिका अन्य शुल्क साझेदारों के साथ चल रही इसी तरह की वार्ता पूरी कर लेगा। यह सहमति वाशिंगटन में वार्ता समाप्त होने की नौ जुलाई की समय सीमा से एक सप्ताह से भी कम समय पहले बनी। वार्ता में वाणिज्य सचिव जवाद पाल ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व किया, ताकि दीर्घकालिक जवाबी शुल्क साझेदारी को अंतिम रूप दिया जा सके। इस

समझौते से पाकिस्तानी निर्यात, मुख्य रूप से वस्त्र और कृषि उत्पादों पर 29 प्रतिशत शुल्क को पुनः लागू होने से रोकेगा। इस वर्ष की शुरुआत में अस्थायी रूप से रोकी गई शुल्क राहत के समाप्त होने का खतरा था, यदि नौ जुलाई तक कोई प्रगति नहीं हुई। वार्ता से परिचित अधिकारियों ने कहा कि चार दिवसीय वार्ता सफल रही, जिसमें दोनों पक्ष एक व्यापक रूपरेखा पर सहमत हुए। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने पर पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी वस्तुओं 5 विशेष रूप से कच्चे तेल के आयात में वृद्धि हो सकती है, तथा पाकिस्तान के खनन, ऊर्जा और अवसरंचना क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश की संभावना बढ़ सकती है। रेको डिक कोर्पर और गोल्ड माइन तथा संबंधित ऊर्जा अवसरंचना जैसी परियोजनाएं चर्चा का केंद्र बिंदु रहीं। यह सीधे अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से विस्तारित भागीदारी का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।

रोजमर्रा की जरूरत के सामान पर मौसम का असर जून तिमाही में राजस्व वृद्धि दर घटने का अनुमान

एजेंसी

नयी दिल्ली। रोजमर्रा की जरूरत का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली कंपनियों का अनुमान है कि जून तिमाही में उनकी राजस्व वृद्धि प्रभावित होगी।

उनका कहना है कि बेमौसम बारिश, गर्मियों की अवधि कम होना और प्रमुख कच्चे माल पर मुद्रास्फूर्ति का दबाव जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ऐसा हो सकता है। हालांकि, एफएमसीजी उद्योग ने तिमाही के दौरान मांग में क्रमिक सुधार देखा, जिसमें विशेष रूप से शहरी बाजारों में मात्रा के लिहाज से बिक्री तेजी से बढ़ी। मैरिको, डाबर और गोदरेज कंज्यूमर जैसी प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों का मार्जिन मानक स्तर से नीचे रहा, और उनका अनुमान है कि अप्रैल-जून में मात्रा के लिहाज से



कम एक अंकों की वृद्धि होगी। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को उम्मीद है कि जून तिमाही में भारत के करोबार से उसका मार्जिन 'मानक सीमा' से नीचे रहेगा, लेकिन मात्रा के लिहाज से बिक्री बढ़ने के कारण उच्च एक अंकों की मूल्य वृद्धि हो

सकती है। दूसरी ओर डाबर के एकीकृत राजस्व में पेय पदार्थों की बिक्री उम्मीद से कम रहने के कारण कम एक अंकों की वृद्धि होने का अनुमान है। पेय पदार्थों की बिक्री बेमौसम बारिश और छोटी गर्मी के कारण प्रभावित हुई।

जेन स्ट्रीट जैसी प्रॉप दिग्गज कंपनियां पीछे हटी तो खुदरा व्यापार असर संभव: जेरोधा सीईओ

नयी दिल्ली। जेरोधा के संस्थापक और सीईओ नितिन कामथ ने चेतावनी दी है कि अगर जेन स्ट्रीट जैसी प्रोपराइटी ट्रेडिंग फर्म बाजार में अपनी भागीदारी कम करती हैं, तो खुदरा व्यापार गतिविधि प्रभावित हो सकती है। गौतमलब है कि ये फर्म विकल्प कारोबार में मात्रा के लिहाज से लगभग 50 प्रतिशत का योगदान देती हैं। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम का शेयर बाजारों और ब्रोकरों, दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कामथ ने एक्स पर कहा, जेन स्ट्रीट जैसी प्रॉप ट्रेडिंग फर्म का ऑफ़शन कारोबार में मात्रा के लिहाज से लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं। अगर वे पीछे हटती हैं, जो संभावित लगता है, तो खुदरा गतिविधि (करीब 35 प्रतिशत) भी प्रभावित हो सकती है।

एजेंसी

अधिक दोपहिया वाहन हैं, इसलिए सवार की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है। विभाग ने बताया कि घटिया हेलमेट की बिक्री सुरक्षा से समझौता करती है। वर्ष 2021 से एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू है, जिसके तहत सभी दोपहिया वाहन चालकों के लिए बीआईएस मानकों के तहत प्रमाणित आईएसआई-चिह्नित हेलमेट अनिवार्य है। जून 2025 तक, पूरे भारत में 176 विनिर्माता हैं, जिनके पास सुरक्षात्मक हेलमेट के लिए वैध बीआईएस लाइसेंस हैं। बयान में कहा गया, हर्बिवाग ने पाया है कि सड़क किनारे बेचे जाने वाले कई हेलमेट में अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन का अभाव है, जिससे उपभोक्ताओं को



काफी जोखिम होता है और सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत हो जाती है। गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए, बीआईएस नियमित रूप से कारखाने और बाजार की निगरानी करता है। पिछले वित्त वर्ष के

दौरान, 500 से अधिक हेलमेट नमूनों का परीक्षण किया गया और बीआईएस मानक चिह्नन के दुरुपयोग के लिए 30 से अधिक तलाशी और जब्त अभियान चलाए गए। दिल्ली में एक अभियान में, नौ विनिर्माताओं से

2,500 से अधिक गैर-अनुपालन वाले हेलमेट जब्त किए गए, जिनके लाइसेंस समाप्त हो चुके थे या रह कर दिए गए थे। अभियान में 17 खुदरा और सड़क किनारे के स्थानों पर इसी तरह की कार्रवाई में लगभग 500 घटिया हेलमेट जब्त किए गए। इससे पहले, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जिला कलेक्टरों (डीसी) और जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने और दोपहिया सवारों के लिए गैर-अनुपालन वाले हेलमेट बेचने वाले विनिर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए लिखा था। बीआईएस शाखा कार्यालयों को इस अभियान को सहयोग देने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभागों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

स्वामी मुद्रक प्रकाशक एवं सम्पादक हरिनाथ सिंह द्वारा टिनटिन प्रिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड डी-33 अमौसी इण्डस्ट्रीयल एरिया, नादरगंज, लखनऊ से मुद्रित एवं 1/39 प्रथम तल करामत मार्केट निशातगंज, लखनऊ से प्रकाशित, सम्पर्क-522-4064242
Email: noidarp@gmail.com, therptimes@yahoo.com, 9918735329
***** इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.पी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

सूचना

पाठकों को सुझाव दिया जाता है, कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पहले स्वयं उचित जाँच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद या सेवा हेतु किये गये किसी दावे की साई का आशवासन नहीं देता तथा ऐसे विज्ञापनों पर विश्वास करके किसी भी व्यक्ति को हुई क्षति, हानि, परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

लघु संविधान-जरूरत या गलती

आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में किए गए संशोधन को लेकर खिड़ी बहस



लखनऊ। देश में इस समय भारतीय संविधान बनाम लघु संविधान की बहस छिड़ी हुई है। संघ नेता दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान के बाद दोनों तरफ से सियासी तलवारें खिंच गई हैं। भाजपा और संघ परिवार जहां इसे ऐतिहासिक गलती बता रहा है, वहीं कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर भाजपा को संविधान विरोधी बताने में जुटा है। दोनों तरफ से बार-फलटवर जारी है। संसद के मानसून सत्र में भी अलग मुद्दों के साथ यह मुद्दा भी जोरदारी से उठाए जाने की संकेत दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष को लगता है कि जिस प्रकार उसने 2०24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को संविधान विरोधी बताकर उसे कमजोर किया है, ठीक उसी तरह इस बार भी बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनावो किया जा सकता है। इसीलिए विपक्ष ने इस मुद्दे को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। दूसरी तरफ भाजपा आपातकाल के समय में संविधान के प्रस्तावना में किए गए इस संशोधन को ऐतिहासिक

संपादक मण्डल

- संस्थापक/संरक्षक
- संजीव श्रीवास्तव
- प्रधान संपादक
- हरिनाथ सिंह
- समूह संपादक
- डॉ. सुशीलचन्द्र त्रिवेदी ‘मधुपेश’
- स्थानीय संपादक
- दिनेश कुमार गर्ग
- सलाहकार संपादक
- डा. एम.ए.ए.खान (लखनऊ)
- (आई.ए.एस. से.नि.)
- डा. ओम प्रकाश
- (आई.ए.एस. से.नि.)

- स्थानीय संपादक नोएडा/एनसीआर
- समन्वय संपादक
- आशुतोष रंजन
- समन्वय संपादक/महाप्रबंधक
- अनिल तिवारी
- साहित्यक संपादक
- आर.पी. शुक्ल, आई.ए.एस.(से.नि.)
- आध्यात्मिक संपादक
- श्री राम महेश मिश्र
- सह संपादक
- ताहिर इकबाल
- आई.ए.एस (से.नि.)
- सह संपादक
- मेजर. के. किशोर
- सह संपादक
- हरिशंकर शुक्ल (पी.पी.एस. से.नि.)
- उप सम्पादक
- प्रभात वर्मा
- स्टेट क्वार्टिनेटर
- विपिन सोनी
- संपर्क मुख्यालय
- कार्यालय फोन नं. : 0522-46 43988
- www.rashtriyaprastavana.com
- ईमेल : noidarp@gmail.com
- प्रधान कार्यालय : - एफ1/39 प्रथम तल
- करामत मार्केट निशांतगंज लखनऊ,(उप्र)

- संघ नेता दत्तात्रेय होसबोले
- के बयान के बाद देश में
- सियासी भूचाल आने के
- संकेत
- विपक्ष फिर भाजपा को घेरने
- में जुटा, भाजपा इसे
- ऐतिहासिक गलती बताने में
- जुटी
- संसद के मानसून सत्र में भी
- इस मुद्दे लेकर हो हल्ला मचने
- के भी मिल रहे संकेत

भूल बताते हुए इस पर कांग्रेस और तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है। आपातकाल लगाने की तारीख के 50 वर्ष पूरा होने के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान देकर ठहरे पानी में कंकड़ फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जबरदस्ती डाले गए हैं। जबकि संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी और बहुमत से खारिज कर दिया गया था। और बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने अपनी सहूलियत के लिए संविधान का अपमान किया है। जानकारों का कहना है संविधान सभा में यह प्रस्ताव एक सदस्य के टी शह ने रखा भी था, किंतु प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि हमारे संविधान का मूल भाव ही यही है, इसलिए इसको अलग से डालने की कोई जरूरत नहीं है। बताते हैं कि संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को बहुमत से खारिज कर दिया गया था। ऐसे में जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय संविधान संशोधन कर प्रस्तावना में ये दोनों शब्द डाले तो अब उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठने लगे हैं। संघ नेताओं का कहना है कि परिवर्तन बाबा साहेब की मंशा के खिलाफ था, ऐसा करके कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया है। ऐसे में इस पर चर्चा की जरूरत है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने-सामने हैं।

भारत की दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का लघु संविधान यानी भारतीय संविधान का 42 वां संशोधन, इस समय चर्चा में है। चर्चा शुरू हुई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए हैं, और ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मंशा के अनुरूप नहीं है। और अब समय आ गया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। होसबोले के इस बयान को समर्थन देने हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कर दिया है। उन्होंने भी कहा कि आपातकाल में संविधान की प्रस्तावना में हुए संशोधन पर चर्चा होना जरूरी है।

भारत की दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का लघु संविधान यानी भारतीय संविधान का 42 वां संशोधन, इस समय चर्चा में है। चर्चा शुरू हुई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए हैं, और ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मंशा के अनुरूप नहीं है। और अब समय आ गया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। होसबोले के इस बयान को समर्थन देने हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा है कि ये संशोधन न्यायिक समीक्षा से परे रहेंगे। शायद इसीलिए पूर्व सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने भी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते समय कहा था कि चूंकि अब ये

इंदिरा गांधी की सरकार ने पास किया लघु संविधान

दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा संविधान के प्रस्तावना में संशोधन और लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार का प्रस्ताव एक ही तारीख में 18 दिसंबर 1976 को पारित किया गया। हालांकि लोकसभा का एक्सटेशन 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ, जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। इन पारित संशोधनों को न्यायिक समीक्षा से भी अलग रखा गया था। इंदिरा गांधी सरकार ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा। इस संशोधन को ‘लघु-संविधान’ के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा 18 दिसंबर, 1976 को ही इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 18 दिसंबर, 1976 को ही तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। इस संशोधन के माध्यम से, संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार और व्यापक रूप से मिल गया। साथ ही अदालतों को इन संशोधनों की समीक्षा करने से भी रोक दिया गया। तब से इस संशोधन को भारत की राजनीति में एक विवादस्पद घटना के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसने आपातकाल के दौरान सरकार की शक्तियों को और मजबूत किया था। दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार की संस्तुति पर ही भारत के राष्ट्रपति त्रिाशन लगाया था। और यह 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक लगा रहा। इसकी कुल 21 महीने की अवधि थी। इंदिरा सरकार ने तब देश में आंतरिक और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा की थी। अब देश के राजनीतिक इतिहास को बदल देने वाली इस घटना के 50 साल पूरे हो गए हैं। 50 साल वो समय होता है जब दो पीढ़ियां किसी देश के लोकतंत्र का अनुभव हासिल कर परिपक्व हो चुकीं होती हैं। ऐसे में देश इस तारीख को याद कर इसके सबक को आत्मसात कर रहा है। इंदिरा सरकार ने पांचवीं लोकसभा (1971- 1977) का कार्यकाल दो बार एक-एक साल के लिए बढ़ाया था। पांचवीं लोकसभा का गठन 1971 के चुनावों के बाद हुआ था। पहली बार इसे 1976 में एक साल के लिए बढ़ाया गया था। और फिर दूसरी बार 1977 में ही एक साल के लिए बढ़ाया गया। वैसे दूसरी बार का विस्तार पूरा नहीं चल पाया और लोकसभा को 1977 में ही भंग भी कर दिया गया था। इस प्रकार पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल कुल मिलाकर 21 महीने के लिए दो बार में बढ़ाया गया था।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण है 42वां संशोधन

भारतीय संविधान में अब तक 1०6 संशोधन हुए हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। इसके के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के बहुचर्चित 42 वें संशोधन को दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसने संविधान संशोधन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ना, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, और केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ाना शामिल है। इस संशोधन ने 42वें संशोधन के जरिए कुछ विवादस्पद प्रावधानों को पलट दिया गया। इस बदलाव ने आपातकाल की घोषणा के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। संविधान का 42वां संशोधन आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम, 1976 के रूप में जाना जाता है। यह संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। इसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण, विवादस्पद संशोधनों में से एक भी माना जाता है। इस संशोधन ने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। श। इस संशोधन ने संविधान के भाग ऋ-ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। इसी संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया। इसी के जरिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष तक कर दिया गया। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संगठन के साथ उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन किया गया।

संविधान का हिस्सा है, इसलिए इस पर सुनवाई का कोई मतलब है नहीं है। इस टिप्पणी के साथ उन्होंने याचिका खारिज कर दी। बीते 25 जून को आपातकाल लागू होने की तारीख के 50 साल पूरे होने पर संघ नेता होसबोले के बयान के बाद यह मामला एक बार फिर गर्म हो गया है। चुनावी मौसम है, इसलिए भी अधिक बयानबाजी हो रही है। ज्ञात हो कि इसी नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, आगले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव हैं। और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के भी चुनाव हैं। ऐसे में इस पर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। भाजपा और संघ के नेता जहां इस पर चर्चा कराने पर जोर दे रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता भाजपा और संघ पर आरोप लगा रहे हैं कि वे मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं, इनका संविधान में विश्वास नहीं है। उनका आरोप है कि संघ और भाजपा नेता बार-बार संविधान पर चोट करते हैं। विपक्ष ने संविधान की खिलाफत का ही आरोप लगाकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया गया था कि अगर भाजपा को अधिक सीटें मिलीं तो वे संविधान संशोधन कर ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि दलितों , पिछड़ों और वंचितों का अधिकार और आरक्षण छिन जाएगा। विपक्ष ने यह भी आशंका जताई है कि शायद इसके बाद फिर चुनाव ही न हो। विपक्ष इस नैरेटिव से भाजपा को धुक्काना भी हुआ और 400 सीटों की उम्मीद पालने वाली भाजपा को विपक्ष ने 240 सीटों पर ही रोक दिया था। अब इस समय एक बार फिर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विवाद का अंत जहां पर जाकर हो किंतु संघ नेता दत्तात्रेय होसबोले ने इस चुनावी मौसम में यह बयान देकर माहौल गर्मा दिया है। इस पर चर्चा चाहने लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब देश में आपातकाल लगा हुआ था तब ही ये संशोधन क्यों किया गया।

उनका तर्क है कि ऐसी स्थिति में तो सिर्फ आपातकालीन व्यवस्थाएं की जाती हैं। उन्हें स्पष्ट मान लेना संविधान निर्माताओं की मंशा और जनता के साथ धोखा माना जाएगा। इसके अलावा सवाल यह भी उठता है उस समय जब लोकसभा अस्तित्व में नहीं थी, और लगभग पूरा विपक्ष जेल में था तो संविधान संशोधन पास किसने किया। इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का कहना है कि संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़कर बाबा साहेब की सोच और समझ पर भी सवाल उठाए गए हैं। वैसे भी संविधान की प्रस्तावना में इन दोनों शब्दों का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में इनके रहने पर नए सिरे से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसके अलावा एक टीवी चैनल के तात्कालिक सर्वे में भी यह बात सामने आई है कि देश के 75% लोग संविधान से इन दोनों शब्दों को हटाना चाहते हैं। इस सर्वे का सैंपल साइज 20000 का था। बताते हैं कि देश में आपातकाल लागू करने के बाद इंदिरा सरकार ने संविधान के 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में ये दो शब्द जोड़े थे। आरोप यह भी है कि उस समय विपक्ष के अधिकांश नेता जेल में बंद थे। इसीलिए संशोधन की संवैधानिकता पर सवाल उठाया जा रहे हैं।

वैसे देश में जब जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब एक जनहित याचिका दायित्व कर संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गये इन दो शब्दों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इन्हें हटाने की मांग की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने तब कहा था कि चूंकि ये शब्द अब संविधान का हिस्सा हैं, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। जस्टिस खन्ना की पीठ ने वह याचिका खारिज कर दी थी। इस पर कानून के जानकारों का कहना है कि चूंकि

संविधान से खिलवाड़ का आरोप है कांग्रेस पर

देश की सबसे पुरानी और आजादी की लड़ाई से जुड़ी कांग्रेस पार्टी पर आरोप है कि उसने कई मौकों पर संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात किया है। बहुचर्चित शाहबानो केस में तब की दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने संविधान की व्यवस्थाओं के ऊपर शरिया कानून को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए शाहबानो के गुजारा भता के अधिकार को रद्द कर दिया था। इसके अलावा दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ही सरकार ने आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द डाला था। कांग्रेस के समय में ही संविधान में संशोधन कर राष्ट्रपति के अधिकारों को कम किया गया था। उस संशोधन के पूर्व राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सिफारिशों पर अपने विवेक पर निर्णय लेने का अधिकार था लेकिन एक संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। भारतीय राजनीति में इसे एक बड़ा बदलाव माना गया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में ही 1991 में प्लेजेस ऑफ वरशिप एक्ट लाकर मंदिरों और मस्जिदों पर यथास्थिति के लिए 15 अगस्त 1947 की सीमा रेखा बना दी थी। फिलहाल यह कानून चर्चा और न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। कांग्रेस की सरकार में ही वक्फ कानून में संशोधन करके उसे असीमित अधिकार दे दिए गए थे। इस विषय में कुछ काम दिवंगत प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय में और बाकी काम दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में किया गया। वक्फ की इसी मनमानी को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद से कानून पास कर बदलाव किया है। ये कानून भी इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। इस पर सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला सुरक्षित है।

संघ और भाजपा पर भी लगते रहे हैं आरोप

संघ और भाजपा पर भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि उसने संविधान को कभी नहीं माना। यह भी आरोप है कि संघ ने अपने कार्यालय में काफी दिनों तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया। यही नहीं 2024 के आम चुनाव में भी पूरे विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ यह नैरेटिव गढ़कर चुनाव लड़ा कि भाजपा 400 सीट पा जाएगी तो संविधान बदल देगी। और फिर उसके बाद चुनाव नहीं होंगे तथा दलितों, पिछड़ों और गरीबों के हक मार दिए जाएंगे। विपक्ष का यह नैरेटिव सफल भी हुआ और भाजपा 240 सीटों पर आकर सिमट गई थी। भाजपा की इस हार के लिए कुछ भाजपाइयों के बयान भी महत्वपूर्ण रहे, जिनमें कुछ छुटभेया नेताओं ने कहा था कि भाजपा को सरकार चलाने के लिए तो पर्याप्त सीट मिल ही जाएंगे किंतु कुछ बड़े काम करने हैं इसलिए 400 पार सीटें चाहिए। और भाजपाइयों की इसी बात को विपक्ष ने पकड़ लिया और संविधान हटाने का नैरेटिव गढ़कर भाजपा के खिलाफ मजबूत रियंति बना ली।

पक्ष-विपक्ष के क्या हैं विचार

इस बाबत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि उस समय की सरकार को ये अधिकार था कि वह संविधान संशोधन करे, और उसने किया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इमरजेंसी लागू होने भर से सरकार के संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उस समय की जरूरत के हिसाब से उक्त संशोधन किए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस बारे में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिष्ठान राहुल गांधी ने कहा है बीजेपी और आरएफएस को संविधान नहीं, मनुस्मृति के साथ को चलाना है। उनका आरोप है कि बीजेपी की कोशिश है कि वह दलितों, गरीबों को गुलाम बनाकर रखे। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा और संघ के लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़े, दलित और गरीबों को उनका हक मिले। इसीलिए वे संविधान संशोधन की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा कि पर हम जब तक हैं, तब तक उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। लगभग यही बात कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने भी कही है। इस बाबत सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी भाजपा और संघ की भंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इनका वश चले तो ये देश के संविधान को ही रद्द कर दें। अखिलेश यादव ने कहा कि जुन 1975 में तो घोषित आपातकाल लागू किया गया था लेकिन इस समय तो भाजपा ने देश में अधोषित आपातकाल लागू किया हुआ है। लोगों के साथ जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म से धर्म और जाति से जाति को लड़ाकर नकारात्मक राजनीति करती है। जबकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो सुश्री मायावती ने कहा है कि अगर संविधान से छेड़छाड़ की कोशिश होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने मन की बात कार्यक्रम में इस मुद्दे पर कहना है कि इमरजेंसी के दौरान देश में संविधान की हत्या हुई। इस दौरान लोगों को प्रताड़ित किया गया। उन्होंने पूछा कि कल्पना कीजिए कि वो दौर कैसा रहा होगा। लेकिन आपातकाल में देश की जनता ना झुकी, ना टूटी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि संविधान को जेब में रखकर घूमने वाले लोगों ने इसका सर्वाधिक नुकसान किया है। भारत के संविधान की मूल भावना को नष्ट करने का काम ऐसे ही लोगों ने किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि होसबोले जी ने जो कहा है, वह 200 परसेंट ठीक है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा है कि संविधान का अपमान करने वाले लोग संविधान की बात न करें तो ही बेहतर है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान से बहुत छेड़छाड़ किया है। उन्होंने कहा कि आपातकाल में तो कांग्रेस ने संविधान की बुनियाद ही हिला दी। इस बाबत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये देश कभी भी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है। इस शब्द को डालकर बाबा साहेब की सोच पर सवाल उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया। 15 मार्च 1976 को लोकसभा कार्यकाल खत्म हो गया और 2 नवंबर 1976 को संविधान में सेक्युरर जोड़ दिया। उनका कहना है कि जब लोकसभा का कार्यकाल ही खत्म हो गया तो संविधान संशोधन के लिए वोट किसने दिया। उन्होंने कहा कि यदि आपातकाल गलत है तो 42वां संविधान संशोधन सही कैसे हो गया।

याचिका पर सुनवाई करते समय ये दोनों शब्द संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा थे, इसलिए जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ कुछ नहीं कर सकती थी।? अब दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद अब एक बड़ी बहस छिड़ गई है। पूरा विपक्ष भाजपा-संघ को संविधान विरोधी बताकर उनकी मंशा पर सवाल उठाने लगा है। पर, इस मामले में एक सवाल तो उठता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अनुयाई बनने वाली कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल क्या बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान को बदलकर बाबा साहेब को गलत साबित करना चाहते हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या भाजपा और संघ इस मामले में बाबा साहेब द्वारा बनाए मूल संविधान को स्थापित करके बाबा साहेब के समर्थकों की सहायुभूति जुटाना चाहते हैं। जहां तक संविधान की

अवहेलना की बात है तो कांग्रेस पर आरोप है कि उसकी सरकारों ने देश की चुनी हुई लगभग 75 राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर बर्खास्त कर दिया था। इसलिए अब कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने वाली कांग्रेस भी संविधान की बात करे तो हास्यास्पद लगता है। आरोप है कि संविधान को जेब में रखकर उस पर अमल न करने वाले राहुल गांधी अगर संविधान की रक्षा की बात करें तो हास्यास्पद लगता है। आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान की मूल भावना को खत्म कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को चोट पहुंचाया है। और जब ऐसी पार्टी संविधान की रक्षा की बात करता है तो सवाल उठना लाजिमी है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को जयंती पर याद किया

बिजनौर। सामाजिक न्याय के योद्धा, पद्म भूषण से सम्मानित, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. रामविलासपासवान की जयंती नगर की वाल्मीकि बस्ती स्थित धर्मशाला में शनिवार को मनाई गई। इस अवसर पर स्व. रामविलास पासवान को स्मरण करते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पार्टी के जिला अध्यक्ष रामनाथ सिंह ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान दलित, शोषित और सर्वहारा वर्ग की लड़ाई आयु पर्यंत लड़ते रहे। आज उनकी जयंती पर हम संकल्प लें कि हम उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। जिला प्रवक्ता वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान अपनी युवावस्था से ही एक जुझारू तथा जमीन से जुड़े नेता रहे। उन्होंने पूरे राजनीतिक जीवन में सदैव वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। बिजनौर से उनका गहरा नाता रहा। उनके द्वारा जलाई हुई मशाल को हमें आगे ले जाना है और वंचितों और शोषितों को उनका अधिकार दिलाने में तन, मन से काम करना है। जिला महासचिव यादराम सिंह ने स्वर्गीय पासवान द्वारा बिजनौर में लड़े गए चुनाव को याद किया और उनकी विचारधारा पर चर्चते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का आह्वावन किया। इस अवसर पर भ्रष्टाचार विरोधी एवं प्रगतिशील मंच के अध्यक्ष के के रंजन ने भी दिवंगत नेता की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित किए और उनके कार्यों का स्मरण किया।

छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रांति में बम की सूचना से मचा हड़कम्प

यात्रियों ने करीब 400 किमी तक की दहशत में यात्रा

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यून नेटवर्क

झांसी। हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग जा रही छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस (12824) में बम की खबर पर सनसनी फैल गई। ट्रेन के वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर पहुंचने पर सभी कोच को खाली करावा कर लगभग एक घंटा आरपीएफ, जीआरपी, बम निरोधक दस्ता, डाग स्वाययड द्वारा छानबीन की गई। जब बम नहीं मिला तब जाकर राहत की सांस ली गई और ट्रेन को खाना दिया गया। झांसी में घटनाक्रम ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि सूचना दिल्ली से चलने के बाद दी गई थी, किंतु दिल्ली से झांसी के बीच कई बड़े स्टेशन होने के बावजूद भी ट्रेन को कहीं भी रोककर चेक नहीं किया गया। करीब 400 किमी तक लोगों ने मौत की दहशत में यात्रा की। दरअसल, हजरत निजामुद्दीन से चलकर दुर्ग जाने वाली छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस (12824) हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से शुक्रवार सायं 5.55 बजे खाना हुई। ट्रेन चलने के लगभग 10 मिनट बाद रेल मदद पर सूचना दी गई कि ट्रेन के स्लीपर कोच में बम है। सूचना देने वाले ने खुद को रेल उपयोगकर्ता बताया

था। लेकिन जब तक सूचना मिली ट्रेन अपना स्टेशन छोड़ चुकी थी। इसके बाद अगला स्टॉपज 400 किमी दूर वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन था, किंतु रेल मशीनों की लापरवाही के चलते ट्रेन को फरीदबाद, मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े स्टेशन पर रोक कर चेकिंग की जरूरत महसूस नहीं की गई और सर्च के लिए 400 किलोमीटर दूर ट्रेन का अगला स्टॉपज वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन तय किया गया। झांसी में सुरक्षा मशीनों सतर्क हो गईं और ट्रेन आने से पहले सुरक्षा बलों ने प्लेटफॉर्म नंबर दो को खाली करावा कर छवनी में तब्दील कर दिया। छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसे ही अपने निर्धारित समय से 9 मिनट की देरी से रात 11.31 बजे प्लेटफॉर्म में पहुंची तो यहाँ पहले से मौजूद सिटी मॉजस्ट्रेट प्रमोद झा, एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार, आरपीएफ कमांडेंट विवेकानंद नारायण और स्टेशन डायरेक्टर सीमा तिवारी ने जितने की पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ, डॉग स्वाययड और बम निरोधी दस्ते के साथ कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रेन के सभी कोच लगेज सहित तुरंत खाली कराए गए।